

Title Code:- UPBIL05169

वक्फ डुडे

हिन्दी/उर्दू मासिक पत्रिका

वर्ष : 01

अंक : 03

दिसम्बर, 2021

मूल्य : ₹25



वक्फ संपत्ति को अवैध कब्जे से मुक्त कराने की प्रतिबद्धता



न्यूनतम समर्थन मूल्य लाभाकारी बने

Title Code:- UPBIL05169

हिन्दी/उर्दू मासिक पत्रिका

वक्फ टुडे

वर्ष : 01 अंक : 03, दिसम्बर, 2021
पृष्ठ : 32 लखनऊ मूल्य : 25 ₹

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक जावेद अहमद द्वारा
स्काई लाइन प्रिन्टर्स, 119/23 अल्वी हाउस,
खण्डारी लेन, लालबाग, लखनऊ, (उ०प्र०) से
मुद्रित तथा फ्लैट नं. एस-1, सेक्रेण्ड प्लोर,
98 शबनम बिल्डिंग, नजरबाग, लखनऊ,
226001 (उ०प्र०) से प्रकाशित।

सम्पादक

जावेद अहमद

मो०नं०: 7054337542
9811010004

E-mail: waqftoday@gmail.com

पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचारों के
संकलन एवं चयन के लिए उत्तरदायी।

नोट- किसी भी विवाद के लिए न्याय
क्षेत्र लखनऊ ही मान्य होगा।

क्रिसमस डे एवं नव वर्ष के
शुभ आगमन पर समस्त सुधी
पाठकों, विज्ञापनदाताओं एवं
समाचार पत्र प्रतिनिधियों को
“**वक्फ टुडे**”

(हिन्दी/उर्दू मासिक) पत्रिका
परिवार की ओर से हार्दिक बधाई
एवं शुभकामनाएं।

- सम्पादक

**वक्फ टुडे हिन्दी/उर्दू पत्रिका के सफल प्रकाशन पर उत्तर प्रदेश
सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं**

वक्फ टुडे पत्रिका के प्रकाशन पर उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं

वक्फ अधिनियम 1995 द्वारा औकाफ के मुतवल्लीयों और प्रबंध समितियों के उत्तरदायित्व

धारा 36 के अंतर्गत वक्फ का पंजीकरण

- प्रत्येक वक्फ, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व सूचित किया गया हो या उसके पश्चात, बोर्ड के कार्यालय में रजिस्ट्रार किया जायेगा।
- वक्फ के पंजीकरण के लिए आवेदन मुतवल्ली/प्रबंध समिति या वक्फ के वंशजों या हितधारी किसी भी मुसलमान द्वारा किया जा सकेगा।
- पंजीकरण के लिए आवेदन बोर्ड कार्यालय अथवा बोर्ड की वेबसाइट (<https://upsunniwaqfboard.org>) से रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड अथवा प्राप्त कर नियमानुसार किया जायेगा।
- प्रत्येक आवेदन/रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ वक्फ-नामा की एक प्रति अथवा यदि ऐसा कोई वक्फ-नामा निष्पादित नहीं किया गया है या उसकी प्रति प्राप्त नहीं की जा सकती तो उसमें वक्फ के अस्तित्व, उसके स्वरूप और उसके उद्देश्यों की पूरी विवेचनाएं होंगी जहाँ तक आवेदक को शात हो।

धारा-42: वक्फ के प्रबंध में किये गए परिवर्तन के सम्बन्ध में

- बोर्ड में पंजीकृत वक्फ में यदि किसी वक्फ के मुतवल्ली/प्रबंध समिति के सदस्यों की मृत्यु या हस्तक्षेप दिए जाने या हटाए जाने के कारण प्रबंध में किसी परिवर्तन की दशा में, नया मुतवल्ली/प्रबंध समिति, बोर्ड को उस परिवर्तन के बारे में तुरन्त सूचित करेगा।

धारा-44 के अंतर्गत वक्फ का बजट

- वक्फ का प्रत्येक मुतवल्ली/ प्रबंध समिति अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट तैयार कर 28 फरवरी तक बोर्ड को प्रेषित करेगा, जिसमें उस वित्तीय वर्ष के दौरान अनुमानित आय एवं व्यय का विवरण दर्शाया जायेगा।

धारा 46 के अंतर्गत वक्फ के लेखा(औ/अकाउंट) का विवरण के सम्बन्ध में

- प्रत्येक वक्फ का मुतवल्ली/प्रबंध समिति वक्फ से सम्बंधित नियमित लेखा-जोखा रखेगा तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्राप्त और व्यय का पूरा और सही लेखा(अकाउंट) विवरण तैयार कर प्रत्येक वर्ष 30 जून तक बोर्ड को प्रेषित करेगा।

धारा 50 के अंतर्गत मुतवल्लीयों/ प्रबंध समितियों के कर्तव्य

- बोर्ड के निर्देशों को इस अधिनियम के अनुसार कार्यान्वित/पालन करेगा;
- ऐसे विवरण और ऐसी जानकारी या ऐसे ब्योरे प्रदान करे जो बोर्ड द्वारा समय समय पर मांगे/चाहे जाएं;
- वक्फ सम्पत्तियों, लेखा(औ/अकाउंट) या अभिलेखों और सम्बंधित दस्तावेजों का निरीक्षण की अनुमति;
- सभी शोक-देवों का भूगतान करें
- ऐसा कोई अन्य कार्य करें जिसे करने के लिए इस अधिनियम में अपेक्षा की गयी हो।

धारा 72 के अंतर्गत बोर्ड को देय वार्षिक अंशदान

- प्रत्येक ऐसे वक्फ का मुतवल्ली/प्रबंध समिति, जिसकी वार्षिक आय पांच हजार से कम नहीं है, बोर्ड द्वारा प्रदान की गयी सेकओं के लिए बोर्ड को नियमानुसार अंशदान अदा करेगा।

वक्फ संपत्ति पट्टा नियम 2014 (संशोधित 2020)

किसी भी वक्फ संपत्ति को किराये/पट्टा करते समय वक्फ संपत्ति पट्टा नियम- 2014 (संशोधित 2020) का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त वक्फ सम्पत्तियों पर अनाधिकृत कब्जा भी एक बड़ी समस्या है, जिसे हटाए/रोके जाने का प्राविधान वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 54 में है जेकि एक जटिल और लम्बी प्रक्रिया है इस लिए अनाधिकृत कब्जे की बेदखली की त्वरित कार्यवाही हेतु उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-ग्रहादि (अप्रधिकृत अध्यासियों की बेदखली) (संशोधन) अधिनियम 2014 में प्राविधान किया जा चुका है जिस सम्बन्ध में बोर्ड को आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।

जुफर अहमद फारुकी

अध्यक्ष

उ.प्र. सुन्नी सेंट्रल

वक्फ बोर्ड,

लखनऊ



बहुरूपिया वायरस

अब जब कोरोना संक्रमण के नए मामले काफी हद तक काबू में नजर आ रहे थे और देश में तीसरी लहर की आशंका कमजोर पड़ती जा रही थी, अचानक इस वायरस के एक नए वैरिएंट ने फिर खतरे की घंटी बजा दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों को पत्र लिखकर आगाह किया है। खासकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। इस नए वैरिएंट बी.१.१.५२९ की पहचान पिछले हफ्ते साउथ अफ्रीका में हुई। हालांकि इसके मामले अभी ज्यादा नहीं हैं, प्रभावित इलाके भी सीमित ही हैं। इसके बावजूद अगर इस नए वैरिएंट को इतनी गंभीरता से लिया जा रहा है तो उसकी वजह है इसमें दिखे अप्रत्याशित रूप से ज्यादा म्यूटेशन। विशेषज्ञों के मुताबिक, इस वैरिएंट में करीब ५० म्यूटेशन देखे गए हैं, ३० से अधिक तो सिर्फ स्पाइक प्रोटीन में हैं। ध्यान रहे, ज्यादातर वैक्सीन स्पाइक प्रोटीन को ही निशाना बनाती हैं। इसी के सहारे वायरस मानव शरीर की कोशिकाओं तक अपनी पहुंच सुनिश्चित करता है। जाहिर है, स्पाइक प्रोटीन में इतने सारे म्यूटेशन से यह सवाल खड़ा हो गया है कि पता नहीं अब तक उपलब्ध तमाम टीके वायरस के इस नए वैरिएंट पर किस हद तक कारगर होंगे, होंगे भी या नहीं। बोत्सवाना में ऐसे लोग भी इससे संक्रमित हुए हैं, जो टीके के सभी आवश्यक डोज ले चुके हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह संक्रमण हवा के जरिए भी फैल सकता है। हांगकांग में होटल के अलग-अलग कमरों में ठहरे लोगों के स्वेब में इसकी मौजूदगी से लगता है कि इसके फैलने के लिए लोगों का एकदम पास आना या किसी तरह से इसके स्पर्श में आना जरूरी नहीं है। सच है कि इस नए वैरिएंट की नुकसान पहुंचाने की क्षमता और इस पर काबू पाने के तरीकों का पता करने के लिहाज से ये जानकारीयां नाकाफी हैं। मगर इसी वजह से सावधानी और ज्यादा जरूरी हो जाती है। खतरा यह बन गया है कि कहीं जाते-जाते भी लौट आने वाली यह महामारी इस बार अब तक के हमारे सारे प्रयासों पर पानी फेरते हुए तमाम टीकों को बेअसर न साबित कर दे। ध्यान रखना होगा कि पिछले करीब दो साल से इसके साये में रहते हुए लोग आजिज आ चुके हैं। यूरोप के कई शहरों में बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर लगाई गई पाबंदियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की खबरें हैं। अपने देश में भी परेशानी भरे लंबे दौर के बाद अब स्थिति सामान्य होने की ओर है। ऐसे में इस आशंका के लिए कोई गुंजाइश नहीं बनने दी जा सकती कि हालात फिर से उतने ही गंभीर हो जाएंगे। इसका एकमात्र तरीका है यह सुनिश्चित करना कि बाहर से आने वाले एक-एक व्यक्ति की बारीकी से जांच करने और सभी आवश्यक कदम उठाने में किसी भी तरह की लापरवाही न हो।

जावेद अहमद

सम्पादक

वक्फ संपत्ति को अवैध कब्जे से मुक्त कराने की प्रतिबद्धता



वक्फ टुडे न्यूज़

कानपुर। वक्फ वेलफेयर फोरम के सेमिनार में मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने वक्फ बोर्ड में मस्जिदों, मदरसों और कब्रिस्तानों की सुरक्षा के साथ ही वक्फ एक्ट के प्रति जागरूकता के लिए पंजीकरण की रूपरेखा पेश की।

देश में ८० प्रतिशत वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा है, जो मुक्त होने पर, उनकी आय में वृद्धि होगी और राष्ट्र के कल्याण के लिए विकास को बढ़ावा मिलेगा।

वक्फ संशोधन अधिनियम वक्फ संपत्तियों को कब्जे से मुक्त करने के लिए काफी मजबूत है। जिसके इस्तेमाल से माफिया के खिलाफ भी केस दर्ज किया जाएगा। ये विचार मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने वक्फ वेलफेयर फोरम के बैनर तले स्कॉट एक्सचेंज सिविल लाइंस में आयोजित एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए व्यक्त किए।

संगोष्ठी की अध्यक्षता पूर्व आईआरएस

अधिकारी इकराम अल-जब्बार खान ने की, जबकि उर्दू अरबी विश्वविद्यालय के पूर्व आईएएस अधिकारी वाइस चांसलर अनीस अंसारी ने विशेष अतिथि के रूप में भाग लिया।

अनीस अंसारी ने अपने संबोधन में सच्वर कमेटी के हवाले से कहा कि वक्फ संपत्तियों से होने वाली आय १६.२ करोड़ है जबकि वक्फ की ८० फीसदी संपत्तियों पर अवैध कब्जा है। अवैध कब्जाधारियों को हटाने और राजस्व बढ़ाने के लिए जिला स्तरीय निरीक्षण समिति के गठन करना बहुत जरूरी है।

वक्फ वेलफेयर फोरम (पंजीकृत) अध्यक्ष जावेद अहमद ने कहा कि वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए जागरूकता कारवां आज कानपुर पहुंच गया है और जिला स्तर पर स्वैच्छिक पर्यवेक्षी समिति का गठन किया जा रहा है, जिसके तहत हर संभव मार्गदर्शन एवं सहयोग दिया जायेगा।

वक्फ संपत्तियों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने की प्रक्रिया में दिया गया नया पंजीकरण। हेल्पलाइन सेंटर एक टोल फ्री नंबर भी होगा, जिस पर लोग कहीं से भी संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और वक्फ के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

वक्फ संपत्तियों को अवैध कब्जे से मुक्त करने की प्रक्रिया के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम २०१३ बहुत मजबूत और सहायक है, लेकिन आमतौर पर लोगों को ज्ञान और जागरूकता की कमी के कारण इसका लाभ नहीं मिलता है। संशोधन अधिनियम के तहत वक्फ संपत्तियों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के साथ ही टीपी एक्ट के तहत भू-माफियाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मदरसों, मस्जिदों और कब्रिस्तानों की सुरक्षा के लिए वक्फ में पंजीकरण और



संरक्षण के नियमों को जानना जरूरी है. वक्फ वेलफेयर फोरम का मुख्य उद्देश्य वक्फ बोर्ड में मस्जिदों, मदरसों और कब्रिस्तानों की भूमि के पंजीकरण के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना और वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए जिला स्तरीय निगरानी समिति का गठन करना भी है। किया हुआ

काजी शहर हाफिज़ अब्दुल क़दोस हादी ने कहा कि शहरों और उसके आसपास वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे की समस्या बेहद चिंताजनक है. साथ ही, घातममपुर, बाराबंकी और कई अन्य घटनाएं मस्जिदों, मदरसों और कब्रिस्तानों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदमों का संदेश जल्द से जल्द देती हैं। इसके लिए वक्फ वेलफेयर फोरम के प्रयास सराहनीय हैं।

सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. शमीम अहमद ने कहा कि वक्फ संपत्ति की रक्षा के लिए हर जिले में जिलाधिकारी, सहायक आयुक्त और डीएम आपकी मदद कर सकते हैं. पूर्व आईआरएस इकराम अल-जब्बार खान ने अपने अध्यक्षीय भाषण में वक्फ संपत्ति के बारे में विस्तार से बताया और इसकी सुरक्षा के लिए उपयोगी सलाह दी।

संगोष्ठी के निदेशक मोहम्मद खालिद थे। इस अवसर पर मुहम्मद सुलेमान, चौधरी रियाज-उद-दीन सिद्दीकी, एडवोकेट अब्दुल माही खान, एडवोकेट अयाज अहमद, जावेद अहमद सहित बड़ी संख्या में मुस्लिम बुद्धिजीवी मौजूद थे।

फिर से शुरू की जाए जीनोम सिक्वेंसिंग, सीएम योगी ने कोविड नियंत्रण को लेकर हुए बैठक में दिए निर्देश

प्रदेश में अब हर स्तर पर कोविड के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि कोविड वायरस की जीनोम सिक्वेंसिंग फिर से शुरू की जाएगी। कोविड नियंत्रण को लेकर उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि के जीएमयू और एसजीपीजीआई के अलावा बीआरडी गोरखपुर, एलएलआर मेडिकल कॉलेज मेरठ और महारानी लक्ष्मी बाई मेडिकल कॉलेज झांसी में भी जीनोम सिक्वेंसिंग की व्यवस्था सुचारु की जाए। जिससे हर इलाके के सैंपल भेजने में आसानी रहे। उन्होंने कहा कि दूसरे देशों और प्रदेशों से यूपी पहुंचने वाले हर व्यक्ति की कोविड जांच की जाए। इसके लिए बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन व एयरपोर्ट पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है। केंद्र सरकार



की गाइडलाइन को लागू किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर विकास और

क्रियाशील हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए वैरिएंट के मद्देनजर टीकाकरण की गति बढ़ाने की जरूरत है। घर-घर जाकर सर्वेक्षण किया जाए। अब तक पहली डोज न पाने वालों की अलग सूची तैयार कराएं। जिनके दूसरे डोज का समय निकल गया है, उनकी अलग सूची बनाई जाए। दिव्यांग, अक्षम, निराश्रित व वृद्धों से संपर्क कर उनका टीकाकरण कराएं। सीएमओ स्तर से ग्राम प्रधानों, पार्षदों का सहयोग लिया जाए। अधिकारियों ने बताया कि अब तक ४.९५ करोड़ लोगों को टीके की दोनों डोज और ११.१६ करोड़ लोगों ने टीके की पहली डोज प्राप्त कर ली है।

ग्राम्य विकास विभाग प्रदेश में स्वच्छता व सैनिटाइजेशन कार्य तेजी से कराएं। निगरानी समितियों को सक्रिय करें, जिससे संक्रमितों की समय से पहचान और समय पर इलाज हो सके। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि अब तक ५२४ आक्सीजन प्लांट

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित किया कि निराश्रित गो आश्रय स्थल, धान कर्तय केंद्र और खाद खरीद को लेकर कृषि उत्पादन आयुक्त नियमित समीक्षा करें। डीएपी खाद को लेकर भी लगातार समीक्षा की जाए।

अविवेकपूर्ण टिप्पणी संदिग्ध व्याख्याओं को जगह देती है: राष्ट्रपति ने न्यायाधीशों से कहा

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि अविवेकपूर्ण टिप्पणी भले ही अच्छे इरादे से की गई हो, वह न्यायपालिका के महत्व को कम करने वाली संदिग्ध व्याख्याओं को जगह देती है। उच्चतम न्यायालय द्वारा आयोजित संविधान दिवस कार्यक्रम के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कोविंद ने कहा कि न्याय वह महत्वपूर्ण आधार है, जिसके चारों ओर एक लोकतंत्र घूमता है, तथा यह तब और मजबूत होता है जब राज्य

की तीन संस्थाएं- न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका- एक सामंजस्यपूर्ण ढंग से अस्तित्व में होती हैं। राष्ट्रपति ने कहा, संविधान में, प्रत्येक संस्था का अपना परिभाषित स्थान होता है जिसके भीतर वह कार्य करती है।" उन्होंने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायपालिका ने अपने लिए उच्चतम मानक स्थापित किया है। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी एक बयान में कोविंद के हवाले से कहा गया, "इसलिए, न्यायाधीशों का यह भी दायित्व है कि वे अदालत कक्षों में अपने बयानों में अत्यधिक विवेक का प्रयोग करें। अविवेकपूर्ण टिप्पणी, भले ही अच्छे इरादे से की गई हो, न्यायपालिका के महत्व को कम करने वाली संदिग्ध व्याख्याओं को जगह देती है।" कोविंद ने कहा कि लोग न्यायपालिका को सबसे भरोसेमंद संस्था मानते हैं। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर न्यायाधीशों के खिलाफ की जाने वाली टिप्पणियों पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, "...सोशल मीडिया मंचों पर न्यायपालिका के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों के कुछ मामले सामने आए हैं। इन मंचों ने सूचनाओं को लोकतांत्रिक बनाने के लिए अद्भुत काम किया है, फिर भी उनका एक स्याह पक्ष भी है। इनके द्वारा दी गई नाम उजागर न करने की सुविधा का कुछ शरारती

तत्व फायदा उठाते हैं। यह पथ से एक भटकाव है, और मुझे उम्मीद है कि यह अल्पकालिक होगा।" राष्ट्रपति ने कहा कि इस तरह के घटनाक्रम के पीछे क्या वजह हो सकती है। उन्होंने कहा, क्या हम एक स्वस्थ समाज की खातिर सामूहिक रूप से इसके पीछे के कारणों की जांच कर सकते हैं। न्याय पाने में खर्च होने वाले धन के मुद्दे पर उन्होंने कहा, "हमारे जैसे विकासशील देश में, नागरिकों का एक बहुत छोटा वर्ग न्याय के लिये



अदालत का दरवाजा खटखटाने का खर्च वहन कर सकता है।" उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि सभी लोगों की कानूनी सहायता और सलाहकार सेवाओं तक पहुंच बढ़े। कोविंद ने कहा कि यह एक आंदोलन या एक बेहतर संस्थागत तंत्र का रूप ले सकता है। राष्ट्रपति ने कहा, निचली अदालतों से लेकर उच्चतम न्यायालय तक, किसी सामान्य नागरिक के लिए शिकायत निवारण प्राप्त करना कठिन होता जा रहा है। कोविंद ने लंबे समय से लंबित मामलों की ओर इशारा करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि सभी हितधारक राष्ट्रीय हित को सबसे ऊपर रखकर कोई रास्ता निकालें। उन्होंने कहा कि वह जानते हैं कि इसके बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है और इस मुद्दे के समाधान के लिए उचित सुझाव दिए गए हैं। राष्ट्रपति ने कहा, फिर भी, बहस

जारी है और लंबित मामलों की संख्या भी बढ़ती रहती है। अंततः, शिकायत करने वाले नागरिकों और संगठनों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। न्याय की गति को तेज करने के लिए क्या किया जा सकता है? स्पष्ट उत्तर सुधार है।" उन्होंने कहा, अब तक के सुझावों और प्रयासों से पता चलता है कि सुधारों के बारे में आम सहमति विकसित करने के वास्ते आवश्यक कदम व्यापक होने चाहिए। लंबित मामलों के मुद्दे

का आर्थिक वृद्धि और विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। अब समय आ गया है कि सभी हितधारक राष्ट्रीय हित को सबसे ऊपर रखकर रास्ता निकालें। इस प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी बड़ी सहायक हो सकती है। कोविंद ने कहा कि महामारी की वजह से न्यायपालिका के क्षेत्र में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को अपनाने में तेजी आई है। राष्ट्रपति ने लंबित मामलों और न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे

में भी बात की और स्पष्ट किया कि उनका दृढ़ विचार है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। हालांकि, उन्होंने पूछा, इसे थोड़ा भी कम किए बिना, क्या उच्च न्यायपालिका के लिए न्यायाधीशों का चयन करने का एक बेहतर तरीका खोजा जा सकता है?

कोविंद ने कहा, उदाहरण के लिए, एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा हो सकती है, जो निचले स्तर से उच्च स्तर तक सही प्रतिभा का चयन कर सकती है और इसे आगे बढ़ा सकती है। उन्होंने कहा कि यह विचार नया नहीं है और बिना परीक्षण के आधी सदी से भी अधिक समय से है। राष्ट्रपति ने कहा, मुझे यकीन है कि व्यवस्था में सुधार के लिए बेहतर सुझाव भी हो सकते हैं। आखिरकार, उद्देश्य न्याय प्रदायगी तंत्र को मजबूत करना होना चाहिए।

चुनाव से पहले बैंकों की 700 नई शाखाएं और 700 एटीएम होंगे स्थापित, राज्य सरकार के प्रस्ताव को केंद्र ने दी मंजूरी

यूपी विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में बैंकों की 700 नई शाखाएं और 700 नए एटीएम स्थापित किए जाएंगे। केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री डा. भागवत किशनराव कराडे की अध्यक्षता में यहां संपन्न राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की विशेष बैठक में यह फैसला हुआ। इससे 23 हजार से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त हो सकेगा। महानिदेशक संस्थागत वित्त शिव सिंह यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ वर्चुअल संवाद में प्रदेश में राष्ट्रीय मानक (एक लाख जनसंख्या पर 18 बैंक) के अनुरूप बैंक शाखाएं व एटीएम स्थापित करने का आग्रह किया था।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस पर कार्रवाई का आश्वासन दिया था। सोमवार को बड़ौदा भवन गोमतीनगर में केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री डा. भागवत किशनराव कराडे की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक हुई। इसमें सभी सार्वजनिक व निजी बैंकों के अधिकारी शामिल हुए। मंत्री ने इसी बैठक में राज्य सरकार के प्रस्ताव पर 700 नई बैंक शाखाएं और इतने ही नए एटीएम 31 मार्च 2022 तक स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। बैंकवार शाखाओं के लक्ष्य भी तय कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि बैंकों ने दिसंबर तक इन बैंक शाखाओं की स्थापना का आश्वासन दिया है। बैठक में राज्य सरकार की ओर से महानिदेशक संस्थागत वित्त यादव के अलावा आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक एलएन राव व राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक बृजेश सिंह आदि उपस्थित थे।

इस तरह बढेंगे रोजगार के अवसर महानिदेशक संस्थागत वित्त ने बताया कि एक बैंक शाखा की स्थापना पर करीब 15 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। इसके अलावा करीब इतने ही बैंक मित्र नियुक्त किए जाते हैं। इस तरह एक शाखा करीब 30 लोगों के लिए सीधे नौकरी या रोजगार का अवसर लाती है। इस तरह बैंक की 700 नई शाखाओं की स्थापना से करीब 21 हजार लोगों को रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसी तरह एक एटीएम पर तीन गार्डों को रोजगार मिलता है। इस तरह करीब 2100 लोगों को गार्ड का काम मिल सकेगा। इस तरह 23 हजार से अधिक रोजगार के अवसर सुनिश्चित करें बैंक



राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में महानिदेशक संस्थागत वित्त शिव सिंह यादव ने बताया कि केंद्रीय मंत्री ने इस संबंध में बैंकों को कार्यवाही के लिए निर्देशित किया है। खन्ना ने नई बैंक शाखाएं व एटीएम की मंजूरी पर पीएम का जताया आभार राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत किशनराव कराडे ने प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। यहां बैठक में लिए गए निर्णयों को साझा किया। खन्ना ने प्रदेश में नई बैंक शाखाओं व एटीएम मशीनों की स्थापना के निर्णय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति धन्यवाद दिया। खन्ना ने कहा कि प्रदेश में नई ब्रांच और एटीएम के खुलने से बैंकिंग सिस्टम मजबूत होगा। इसके अलावा आर्थिक गतिविधियों में विस्तार व रोजगार के अवसर भी बढेंगे।

बढेंगे। मंडल स्तर पर ऋण वितरण मेगा कैंपों को भी मंजूरी राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में महानिदेशक संस्थागत वित्त ने मुद्रा योजना व ओडीओपी योजना के क्रियान्वयन के लिए मंडल स्तर पर मेगा कैंप के आयोजन का प्रस्ताव रखा। केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री ने क्रेडिट आउटरीज प्रोग्राम के अंतर्गत एक दिसंबर से मंडलीय स्तरीय कैंपों के आयोजन संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। उन्होंने बैंकों को इन मेगा कैंपों का आयोजन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। मंत्री ने जनधन खाता धारकों के पास रूपे कार्ड की उपलब्धता बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जिन जनधन खाताधारकों के पास रूपे कार्ड नहीं है, उन्हें अभियान चलाकर उपलब्ध कराया जाए। उन्हें डिजिटल पेमेंट के लिए प्रेरित भी किया जाए। एटीएम पर सुरक्षा गार्डों की तैनाती

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में महानिदेशक संस्थागत वित्त शिव सिंह यादव ने एटीएम से गार्डों को हटाए जाने का मामला भी उठाया। यादव ने बताया कि प्रत्येक एटीएम पर तीन पालियों में एक-एक गार्ड की ड्यूटी होती है। कोविड काल में बैंकों ने एटीएम से गार्ड हटा दिए। इससे करीब 60 हजार गार्डों के सामने रोजगार का संकट आ गया। इसका असर ये हुआ कि एटीएम की सुरक्षा में स्थानीय पुलिस को लगाना पड़ता है। यादव ने बताया कि समिति से एटीएम में प्रशिक्षित गार्डों की तैनाती सुनिश्चित कराने का आग्रह किया गया। इससे न सिर्फ एटीएम की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी बल्कि अनपढ़ व कम टेक्नोसेवी लोगों को डिजिटल पेमेंट के लिए मदद भी दी जा सकेगी। दूसरा, करीब 60 हजार लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो सकेंगे। इसके अलावा खराब एटीएम 24 घंटे में ठीक कराने की व कैश खत्म होते ही उपलब्धता सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया। महानिदेशक ने बताया कि केंद्रीय मंत्री ने इस संबंध में बैंकों को कार्यवाही के लिए निर्देशित किया है।

खन्ना ने नई बैंक शाखाएं व एटीएम की मंजूरी पर पीएम का जताया आभार राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत किशनराव कराडे ने प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। यहां बैठक में लिए गए निर्णयों को साझा किया। खन्ना ने प्रदेश में नई बैंक शाखाओं व एटीएम मशीनों की स्थापना के निर्णय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति धन्यवाद दिया। खन्ना ने कहा कि प्रदेश में नई ब्रांच और एटीएम के खुलने से बैंकिंग सिस्टम मजबूत होगा। इसके अलावा आर्थिक गतिविधियों में विस्तार व रोजगार के अवसर भी बढेंगे।



जिनके पास परिवार नहीं है, वे जनता का दर्द नहीं समझ सकते : अखिलेश

परिवारवाद के आरोप को लेकर अक्सर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के निशाने पर रहने वाले समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को पलटवार करते हुए कहा कि जिनके पास परिवार नहीं है, वे जनता का दर्द नहीं समझ सकते। अखिलेश ने बांदा में एक जनसभा में किसानों की आत्महत्या की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इन किसानों के परिवार की सिर्फ सपा ने ही मदद की है। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कहा, “ हम सब परिवार वाले लोग हैं, इसलिए जानते हैं कि अगर किसी मजदूर या किसान की जान चली गई तो उसके परिवार का क्या हाल होगा ? अगर किसी परिवार के सामने संकट आया, तो हम खड़े हुए। परिवार वाले ही परिवार वालों का दुख दर्द समझ सकते हैं। जिनके पास परिवार नहीं है, वे आपकी परवाह नहीं करेंगे। ” उन्होंने आरोप लगाया कि बांदा में शराब के नशे में एक गरीब को मार दिया गया, लेकिन राज्य सरकार ने पीड़ित के परिवार की कोई मदद नहीं की। सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोगों ने ही उनकी सहायता की।

अखिलेश ने राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि दमदार सरकार चलाने का दावा करने वाले लोग झूठ बहुत ‘दमदार’ बोलते हैं। भाजपा ने

शिक्षामित्रों से नौकरी का वादा किया था, लेकिन अपने साढ़े चार साल के कार्यकाल में इस पार्टी ने नौजवानों के नौकरी के सपने को ही खत्म कर दिया। उन्होंने कहा, “ अब सुनने में आया है कि मुख्यमंत्री नौजवानों को स्मार्टफोन और टैबलेट देंगे। जो लैपटॉप नहीं चला सकता, वह आपको लैपटॉप नहीं दे सकता। क्या मुख्यमंत्री योगी लैपटॉप चला सकते हैं ?

अब तो सुनने में आया है कि वह स्मार्ट फोन भी नहीं चला सकते। अगर चला सकते होते तो हमारे नौजवानों के हाथ में अब तक राज्य सरकार ने स्मार्ट फोन दे दिया होता। आपको योगी योगी सरकार चाहिए, या योग्य सरकार चाहिए ? ” हाल में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) का पर्चा लीक होने की घटना का जिक्र करते हुए सपा अध्यक्ष ने राज्य सरकार पर जानबूझकर पर्चा लीक कराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “ यह सरकार जानबूझकर पेपर लीक कराती है। वह ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वह हमारे नौजवानों को रोजगार नहीं देना चाहती। बीटीसी और बीएड पास नौजवान रोजगार के लिए भटक रहे हैं। हम आपको भरोसा दिला रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार लाइए और नौकरी तथा रोजगार पाइए। ” अखिलेश ने कहा कि बुंदेलखंड

के लोगों ने पिछले कई चुनावों में भाजपा को पूरा समर्थन दिया, लेकिन बुंदेलखंड को कुछ नहीं मिला। इस डबल इंजन की सरकार का इंजन बुंदेलखंड आते-आते फेल हो गया है। सरकार यहां के विकास का कोई इंतजाम नहीं कर पाई, आखिर यह किस बात की डबल इंजन की सरकार है। सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार ने महामारी के समय जनता को अनाथ छोड़ दिया। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने प्रदेश को पीछे कर दिया। राज्य सरकार का विकास तो सिर्फ तस्वीरों में दिख रहा है और इस ‘विकास’ की कलई तस्वीरों और विज्ञापनों ने ही खोल दी। भाजपा के लोग विज्ञापन में भी झूठ दिखाते हैं। नीति आयोग के मुताबिक बुंदेलखंड में ३२ लाख से ज्यादा लोगों के गरीबी रेखा के नीचे होने का जिक्र करते हुए अखिलेश ने वादा किया कि विधानसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर सरकारी बजट से इन गरीबों की मदद की जाएगी, समाजवादी पेंशन योजना से भी अच्छी योजना चलाई जाएगी और महिलाओं तथा परिवारों को पहले से दी जाने वाली ५०० रुपए प्रतिमाह की धनराशि में तीन गुना इजाफा किया जाएगा।

आंबेडकर ने देशवासियों को कम्युनिस्टों से बचकर रहने की दी थी सलाह

अभी-अभी संविधान दिवस बीता है। जब भी संविधान दिवस (२६ नवंबर) आता है या संविधान से जुड़ी बातों पर देशव्यापी विमर्श होता है तब वामपंथी धारा में बहने वाले लेखक और बौद्धिक बाबा साहेब आंबेडकर की कई बातों को संदर्भ से काटकर उद्धृत करते हैं। आंबेडकर के विचारों की आड़ में वो भारत और भारतीयता के साथ साथ हिंदू धर्म और दर्शन पर प्रहार करते हैं। उनके विचारों को इस तरह से पेश करते हैं जैसे कि आंबेडकर हिंदू धर्म के विरोधी थे। वो ये नहीं बताते हैं कि आंबेडकर हिंदू धर्म की कुरीतियों के विरोधी थे और उनका मत था कि इन कुरीतियों को दूर किया जाए। ऐसा करते हुए कम्युनिस्ट इस बात को भी छिपा ले जाते हैं कि उनको लेकर आंबेडकर के क्या विचार थे। मार्क्स और मार्क्सवाद से लेकर उनके अनुयायियों के बारे में बाबा साहेब की सोच क्या थी। १२ दिसंबर १९४५ को नागपुर की एक सभा में आंबेडकर ने देशवासियों को कम्युनिस्टों से बचकर रहने की सलाह दी थी। आंबेडकर ने स्पष्ट रूप से कहा था कि 'मैं आप लोगों को आगाह करना चाहता हूँ कि आप कम्युनिस्टों से बच कर रहिए क्योंकि अपने पिछले कुछ सालों के कार्यों से वो कामगारों का नुकसान कर रहे हैं। वे उनके (कामगारों) दुश्मन हैं, इस बात का मुझे पूरा यकीन हो गया है। कम्युनिस्ट कहते हैं कि कांग्रेस पूंजीपतियों की संस्था है। साथ ही वे कामगारों को उसमें जाने की सलाह भी देते हैं। हिन्दुस्तान के कम्युनिस्टों की अपनी कोई नीति नहीं है, उन्हें सारी चेतना रूस से मिलती है। अपने इस कथन से आंबेडकर ने स्पष्ट कर दिया था कि अपने देश के कम्युनिस्टों की चेतना का आधार रूस से आयातित विचार है और वो कामगारों या मजदूरों को भ्रमित कर कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं। आंबेडकर की ये बातें स्वाधीनता के बाद भी सही साबित हुईं। कम्युनिस्टों को जब भी मौका मिला उन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया, सरकार बनाने से लेकर देश में इमरजेंसी लगाने तक में। आज भी कर रहे हैं। आज जब कम्युनिस्ट पार्टियां अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रही हैं तो उनको कांग्रेस में ही अपना भविष्य नजर आ रहा है। कम्युनिस्ट विचारधारा के अनुयायी लगातार कांग्रेस को मजबूत करने

की बात इंटरनेट मीडिया के अलग अलग मंचों पर लिख रहे हैं। आंबेडकर ने नागपुर की ही सभा में देश के दलितों को भी कम्युनिस्टों से आगाह किया था। आंबेडकर ने कम्युनिस्टों के बारे में कहा था कि 'वे अब हमारे संगठन में घुसकर अपनी हरकतें करने लगे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग कम्युनिस्टों से बचकर रहिए। उन्हें अपने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का उपयोग अपने प्रचार के लिए मत करने दीजिए। अब १९४५ में कहे गए बाबा साहेब के शब्दों पर गौर करें तो स्थिति और स्पष्ट होती है। उनको इस बात की आशंका थी कि अगर कम्युनिस्ट उनके संगठन में घुस गए तो संगठन कमजोर होगा लिहाजा इसलिए वो सार्वजनिक रूप से शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के कार्यकर्ताओं को कम्युनिस्टों की 'हरकतों' से बचकर रहने की सलाह दे रहे थे। आंबेडकर की इन बातों की चर्चा कभी भी कम्युनिस्ट नहीं करते हैं। अपने बौद्धिक विमर्शों में भी आंबेडकर की आलोचना पर ध्यान नहीं देते हैं। बाद के दिनों में या आंबेडकर के निधन के बात तो वो समानता के सिद्धांत के आधार पर उनको भी वामपंथी विचारधारा के करीब दिखाने और प्रचारित करने की कोशिश करते रहते हैं। वामपंथी कभी भी इस बात की चर्चा नहीं करते हैं कि आंबेडकर की राय मार्क्स या उनके सिद्धांतों को लेकर क्या थी। २० नवंबर १९५६ को आंबेडकर का नेपाल में दिया गया एक भाषण है जिसमें उन्होंने बुद्ध और कार्ल मार्क्स पर विचार किया था। अपने उस भाषण में आंबेडकर ने मार्क्सवाद की तुलना में बौद्ध दर्शन को श्रेष्ठ और स्थायी माना है। आंबेडकर ने साम्यवादी जीवन मार्ग और बौद्ध जीवन मार्ग को लेकर अपने विचार रखे थे। उसमें आंबेडकर कहते हैं कि जो जीवनमार्ग अल्पजीवी होगा, गुमराह करनेवाला होगा या अराजकता की ओर ले जानेवाला होगा ऐसे जीवन मार्ग का समर्थन करना उचित नहीं होगा। साफ है कि वो साम्यवादी जीवन मार्ग का निषेध कर रहे थे। उनके इस कथन को नागपुर में कम्युनिस्टों पर व्यक्त किए गए उनके विचारों से जोड़कर देखते हैं तो यह साफ हो जाता है कि कि साम्यवाद के बारे में उनकी राय एक अराजक विचारधारा की रही है और उसको वो भारत के लिए उपयुक्त नहीं मानते

थे। आंबेडकर ने मार्सवादी सोच को व्याख्यायित करते हुए कहा था कि ' साम्यवादी विचारधारा का मूल सूत्र यह है कि दुनिया में शोषण है। यहां अमीरों की ओर से गरीबों का शोषण हो रहा है क्योंकि धनवानों में धन बटोरने की होड़ लगी हुई है। इसी होड़ की वजह से पूंजीपति लोग मेहनतकश वर्ग को गुलाम बना रहे हैं और इसी प्रकार की गुलामी दरिद्रता और निर्धनता का कारण बनती है। कार्ल मार्क्स ने गरीबों के संबंध में या मजदूरों के शोषण के संबंध में सवाल उपस्थित कर अपने साम्यवाद की नींव रखी। लेकिन आंबेडकर इसके सूत्र की तलाश में बौद्ध दर्शन में जाते हैं और वहां से अपनी बात उठाते हैं। उनका मानना है कि बुद्ध दुनिया में दुख की बात करते हैं और बुद्ध ने भी शोषण से पैदा हुए दुख और दरिद्रता के आधार पर अपने दर्शन की नींव रखी। यहां आंबेडकर बहुत स्पष्ट रूप से मानते हैं कि मार्क्स कुछ नया प्रतिपादित नहीं करते हैं बल्कि उनके सिद्धांत के सैकड़ों साल पहले बुद्ध ऐसा कह चुके हैं और इससे मुक्ति का मार्ग भी सुझा चुके हैं। आंबेडकर बुद्ध और मार्क्स के सुझाए मुक्ति के मार्ग के बुनियादी अंतर को भी बहुत साफगोई से जनता के सामने रखते हैं। उनका मानना है कि साम्यवाद की स्थापना के लिए मार्क्सवादियों का रास्ता हिंसा का है और वो अपने विरोधियों को नष्ट कर लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। बुद्ध का रास्ता इससे बिल्कुल अलग है। आंबेडकर के शब्दों को देखते हैं, ' बुद्धिज्म की स्थापना के लिए लोगों के दिलो दिमाग को परिवर्तित करना यही बुद्ध का संवैधानिक रास्ता है। बुद्ध अपने विरोधियों को डरा धमका कर या सत्ता के बल पर पराजित करना नहीं बल्कि प्यार और अपनत्व की भावना से अपना बना लेना है। बाबा साहेब साम्यवाद के गैर संवैधानिक तरीकों को रेखांकित करते हैं और कहते हैं कि साम्यवादी मनुष्य को खत्म करने के सिद्धांत पर अमल करना चाहते हैं लेकिन अगर मनुष्य ही नहीं रहेगा तो न तो कोई प्रतिकार कर पाएगा न ही विरोध तो ऐसी सफलता तो सिर्फ दिखावा बन कर रह जाती है। आंबेडकर ने साम्यवादियों के 'मजदूरों की तानाशाही' (डिक्टेटरशिप आफ प्लोरेतेरियत) और उसको स्थापित करने के खूनी क्रांतिके सिद्धांत को भी कठघरे में खड़ा करते हैं।

आजादी के दीवाने दुर्गामल और दल बहादुर

आजादी के अमृत महोत्सव की कड़ी में हिमाचल प्रदेश के उन दो गोरखा सपूतों का स्मरण आवश्यक है, जिन्होंने आजाद हिंद फौज में रहते हुए कोहिमा में ब्रिटिश सैनिकों को नाकों चने चबाने के लिए बाध्य किया और अंततः फांसी पर झूल गए। मेजर दुर्गामल और कैप्टन दल बहादुर की जड़ें धर्मशाला में थीं और वे छोटी उम्र में ही सेना में भर्ती हो



गये थे। उन्हें दूसरे विश्वयुद्ध में जापान के विरुद्ध लड़ने के लिये भेजा गया था, लेकिन जापान ने ब्रिटेन को पराजित कर सिंगापुर पर कब्जा कर लिया था। जब सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए का गठन किया, तो जापान ने ५० हजार से अधिक हिंदुस्तानी सिपाहियों को रिहा कर दिया, ताकि वे अपने देश की आजादी के लिए ब्रिटिश हुकूमत से लोहा ले सकें। वर्ष १९१३ में देहरादून में जन्मे मेजर दुर्गामल के पिता श्री गंगा राममल भी भारतीय सेना में एक सिपाही थे। युवावस्था में ही दुर्गामल गांधी के सत्याग्रह आंदोलन से प्रेरित थे। १७ साल के इस युवक पर सत्याग्रह का जादू इस कदर हावी था कि वह स्वयं इसमें कूद पड़े। गांधी के इस आंदोलन में उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया। घरवालों ने १९३१ में दुर्गामल को उनके चाचा के पास धर्मशाला भेज दिया और उसी साल वह गोरखा रेजीमेंट में भर्ती हो गये। वह फुटबॉल खिलाड़ी थे और सांस्कृतिक

गतिविधियों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते थे, जिनके बलबूते वह लोकप्रियता के शिखर पर पहुंच गए थे। २८ साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई। वर्ष १९४१ में उनकी यूनिट सिंगापुर पहुंची, जिसे जापानी हुकूमत ने १९४२ में हिरासत में ले लिया। अपने हजारों साथी सिपाहियों के साथ १९४४ में दुर्गामल ने आईएनए में शामिल होने के लिये स्वैच्छिक

सहमति दी। वह आजाद हिंद फौज में मेजर बने और उन्हें सीमा पर जासूसी करने का दायित्व सौंपा गया, ताकि ब्रिटिश फौज की गतिविधियों की सूचनाएं अपने कमांडर को दे सकें। इस काम में उन्हें अपार कामयाबी मिली। लेकिन अंग्रेजों को जब इस बारे में पता चला, तो उन्होंने २७ मई १९४४ को उन्हें कोहिमा में बंदी बना लिया गया। फिर उन्हें लाल किला में हिरासत में रखा गया। उन्हें अनेक प्रलोभन देने के प्रयास किए गए, ताकि वे माफी मांगकर रिहा हो जाएं। लेकिन वह झुकने को तैयार नहीं हुए। वह नेताजी सुभाष के नारे तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा से बेहद प्रभावित थे। पूरी उम्र वह नेताजी के व्यक्तित्व और उनके काम से अभिभूत रहे। जब अंग्रेज दुर्गामल को झुकाने के प्रयास में सफल नहीं हो पाए, तो २५ अगस्त १९४४ को उन्हें लाल किले में ही फांसी पर लटका दिया। गोरखा समुदाय के सुनहरे इतिहास में एक और रणबांकुरे दल बहादुर

की शौर्यगाथा मेजर दुर्गामल से मिलती जुलती है। दुर्गामल की तरह दल बहादुर भी एक सिपाही के बेटे थे और १९०७ में बड़ाकोट, धर्मशाला में पैदा हुए थे। आठवीं पास कर सत्रह साल की उम्र में वह फौज में भर्ती हो गए थे। फौज में बतौर प्रशिक्षु वह बेहद सक्रिय थे। दल बहादुर एक दक्ष खिलाड़ी थे और अपनी निशानेबाजी के लिए विख्यात थे। बाद में वह आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए। न मालूम कितने ही ब्रिटिश फौजियों को कैप्टन दल बहादुर ने जंग में मौत के घाट उतार दिया था। कोहिमा-मणिपुर के घने जंगलों के बीच दल बहादुर ने अपनी टुकड़ी के साथ अंग्रेज सैनिकों से लोहा लिया। आईएनए सैनिकों की वीरता और दम-खम के बलबूते पूर्वोत्तर में यह लड़ाई कई दिनों तक चलती रही। २० जून १९४४ को ब्रिटिश सेना ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और आजाद हिंद फौज को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन दल बहादुर युद्धस्थल पर डटे रहे। आखिरकार ब्रिटिश सेना ने आईएनए के अनेक सिपाहियों के साथ कैप्टन दल बहादुर को भी बंदी बना लिया। दिल्ली में लाल किले में बंदी के रूप में रखने के बाद १२ फरवरी, १९४५ को उन पर मुकदमा चलाया गया। १५ मार्च को उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया। दल बहादुर माफी मांगें, इसके लिए उनकी पत्नी चंपावती पर भी दबाव डाला गया। लेकिन वह अपने पति के फैसले के साथ खड़ी थीं। उनका कहना था, मेरे पति कैप्टन दल बहादुर माफी क्यों मांगेंगे? अपने देश की आजादी के लिए जंग में कूदना क्या कोई अपराध है? अदालत में जब जज ने दल बहादुर को फांसी की सजा सुनाई, तो दल बहादुर ने कहा था, सेना में भर्ती होना मेरा स्वयं का फैसला था। मैं अपने मातृभूमि की आजादी के लिए कोई भी बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। मैंने जो कुछ किया, उस पर मुझे कोई कोई गिला-शिकवा नहीं है। तीन मई, १९४५ को फांसी के तख्ते पर चढ़ते हुए उन्हें एक राष्ट्रीय गीत गुनगुनाते हुए सुनाया गया था। दोनों शहीदों की स्मृति में धर्मशाला के दाड़ी गांव में एक स्मारक का निर्माण किया गया है।

अनुच्छेद ३७० के मुद्दे पर आपस में ही क्यों भिड़ गये हैं उमर अब्दुल्ला और गुलाम नबी आजाद ?



अनुच्छेद ३७० की बहाली की मांग को विपक्ष का समर्थन नहीं मिलने से नेशनल कांफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला भड़क गये हैं और उन्होंने इस मुद्दे पर चुप्पी के लिए कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस अनुच्छेद ३७० की बहाली के लिए लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं है तो उनकी पार्टी अपने दम पर इस लड़ाई को लड़ेगी। उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ३७० हटाने समय केंद्र सरकार ने जो दावे किये थे वह सब खोखले साबित हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पांच अगस्त २०१९ को अनुच्छेद ३७० के अधिकतर प्रावधान हटाने के बाद अखबारों समेत संस्थानों को कमजोर कर भाजपा पर 'लोकतंत्र की हत्या करने' का आरोप लगाया और कहा कि इसने दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के भारत के नारे को झूठ साबित बना दिया है। हम आपको बता दें कि अब्दुल्ला चेनाब घाटी क्षेत्र की यात्रा पर हैं और उन्होंने किश्तवाड़ शहर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, कि (उच्चतम न्यायालय के समक्ष अनुच्छेद

३७० की बहाली के लिए) हमारा मामला बहुत मजबूत है... हमें विपक्षी दलों से समर्थन की उम्मीद थी लेकिन वे चुप हैं। हमारा वजूद इस अनुच्छेद से जुड़ा है। कि इससे पहले उमर अब्दुल्ला ने पार्टी महासचिव अली मोहम्मद सागर सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं के संग हज़रत शाह फरीद-उद-दीन बगदादी और हज़रत शाह असरार-उद-दीन-वली की प्रसिद्ध दरगाहों पर ज़ियारत की और जम्मू कश्मीर में स्थायी शांति व समृद्धि की दुआ मांगी। उधर, कश्मीर में जल्द चुनावों की आहट देखते ही कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद भी सक्रिय हो गये हैं। वह लगातार सभाएं कर रहे हैं और उनका कहना है कि जल्द से जल्द जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाये और इस दर्जे में यह बात भी शामिल हो कि कोई बाहरी यहां की नौकरियां हासिल नहीं कर सके और कोई बाहरी यहां की जमीन नहीं खरीद सके। यही नहीं, उमर अब्दुल्ला द्वारा अनुच्छेद ३७० पर आजाद की टिप्पणी पर निराशा व्यक्त करने के कुछ घंटे बाद आजाद ने कहा कि केंद्र सरकार के पांच अगस्त, २०१९ के फैसले

पर उनका एकजुट, एकल रुख बरकरार है और वह यह है कि इस फैसले के कारण जम्मू-कश्मीर की जनता में व्यापक असंतोष है। आजाद ने कहा कि कश्मीर घाटी में उनके भाषण को मीडिया के कुछ वर्गों ने गलत तरीके से पेश किया। उन्होंने जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने और अगले साल विधानसभा चुनाव जल्दी कराने की अपनी मांग दोहरायी। दूसरी ओर, कश्मीर में कोरोना के सामान्य होते हालात के बीच तीन दिवसीय संभाग स्तरीय कला उत्सव का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय कलाकारों ने भाग लिया। यह कला उत्सव राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा मंत्रालय की ओर से आयोजित कराया जाता है। मंत्रालय की इस पहल का उद्देश्य देश में माध्यमिक स्तर पर स्कूली छात्रों की कलात्मक प्रतिभा को निखारना और उन्हें बढ़ावा देना है। इस कला उत्सव में कश्मीर संभाग के सरकारी और निजी स्कूलों की भागीदारी रही। उत्सव के दौरान ९ विभिन्न श्रेणियों में छात्र-छात्राओं ने भाग लिया और पुरस्कार जीते।

न्यूनतम समर्थन मूल्य लाभकारी बने

एक वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद केंद्र सरकार द्वारा तीनों कृषि कानूनों को संसद के द्वारा खारिज किया जाना किसान आंदोलन की बड़ी उपलब्धि है। महत्वपूर्ण



है कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में वापसी को लेकर अफसोस भी जाहिर किया और क्षमा प्रार्थना की है। आमतौर पर शासन प्रमुख द्वारा इस प्रकार के विनम्रतापूर्वक संबोधन कम ही उपलब्ध हैं, किसान मोर्चा के घटक दलों द्वारा इस निर्णय का स्वागत तो अवश्य किया गया है, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी प्रावधान के तहत लाने की मांग पर कायम रहते हुए उन्होंने धरना खत्म करने का सुझाव खारिज कर दिया है। केंद्र सरकार द्वारा लगभग २३ फसलों के लिए एमएसपी लागू किया गया है, लेकिन एनएसओ की ताजारपट के अनुसार, वास्तविकता यह है कि मात्र पांच फसलें ऐसी हैं, जिनकी १० फीसदी या इससे अधिक पैदावार एमएसपी पर बिक पाती है। प्राप्त आंकड़े बेहद निराशाजनक तस्वीर पेश करने वाले हैं। धान, गेहूँ और गन्ने की ही एमएसपी पर अच्छी बिक्री होती है, लेकिन यह भी अधिकतम चालीस फीसदी दर्ज की गई है।

मसलन, जुलाई-दिसंबर २०१९ के बीच कुल १३ फसलों की एमएसपी पर बिक्री का ब्यौरा एकत्र किया गया है, इसके अनुसार धान की उपज का २३.७ फीसदी,

गन्ने की १८.४ फीसदी, सोयाबीन की १३ फीसदी, उड़द की १.५ फीसदी तथा मूंगफली की १०.९ फीसदी उपज ही एमएसपी के भाव पर बिक पाई है, जबकि आठ अन्य फसलें जिसमें ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, अरहर, मूंग, नारियल तथा कपास शामिल हैं, उनका १० फीसदी हिस्सा भी एमएसपी के भाव नहीं बिक पाया। किसानों के बड़े हिस्से में एमएसपी पर होने वाली बिक्री को लेकर जागरूकता के स्तर में भी कमी पाई गई है। अब किसान संगठनों ने कुछ बुनियादी प्रश्नों को भी उठाना शुरू कर दिया है, जो सरकारी पक्ष के लिए काफी असुविधाजनक साबित हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग ११ करोड़ परिवार कृषि में लगे हैं, इनमें से लगभग ७० फीसदी किसानों के पास एक हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि है। अगर समृद्ध राज्य पंजाब का उदाहरण लें, तो वहाँ एक हेक्टेयर भूमि में लगभग ५० क्विंटल गेहूँ पैदा करने की क्षमता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सीमित सींचित साधनों

के कारण गेहूँ की क्षमता ३५ क्विंटल मात्र आंकी गई है। पंजाब का किसान, सरकारी आंकड़ों के अनुसार फसल से वर्ष में एक हेक्टेयर भूमि में लगभग ३५,००० रुपये मूल्य अर्जित कर पाता है, जबकि उत्तर प्रदेश में किसान को मात्र प्रति हेक्टेयर फसल वर्ष में १५,००० रुपये के मुनाफे से संतोष करना पड़ता है। यह स्थिति उन परिस्थितियों के लिए है, जब सरकार द्वारा घोषित मूल्य पर बिक्री संभव है। निष्कर्ष है कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत समूचे देश के किसानों को मंडी और आढ़ती पर निर्भर रहना पड़ता है और औने-पौने दामों पर ही फसल का निपटारा करना पड़ता है।

खेती और किसानों के संकट का परिणाम है कि लगभग ५२.५ फीसदी किसानों के ऊपर कर्ज का बोझ है। किसान संगठनों का मत है कि जब तक कृषि लागत और मूल्य आयोग को सांविधानिक दर्जा प्राप्त न हो और इसके द्वारा दिए गए सुझाव पूर्णतया मान्य न हों, तब तक इन संस्थाओं का कोई अर्थ नहीं है। यूपीए और एनडीए में शामिल दलों ने अपने घोषणा पत्रों में डॉ. स्वामीनाथन फॉर्मूला लागू कर समर्थन मूल्य तय करने का वादा किया था, जिसे किसी भी शासनकाल में पूरा नहीं किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा महसूस करता है कि सरकार ने जो एमएसपी घोषित की है, उससे तो किसान को अलग-अलग फसलों पर ६११ रुपये से २०२७ रुपये प्रति क्विंटल का नुकसान होगा। सरकारें मूल्य घोषित करते-करते बड़े ढिंढोरे पीटती हैं कि किस प्रकार लाभकारी मूल्य में वृद्धि हुई है, लेकिन घोषणा में सी-२+५० फीसदी के फॉर्मूले को पूरी तरह नजर अंदाज किया जाता है। यही उपयुक्त समय है, जब एक नए किसान आयोग का गठन किया जाए, जिसे अन्य आयोगों की तरह सांविधानिक दर्जा हो और जिसके निर्णय लागू करने के लिए सरकारें बाध्य हों।

अगर एमएसपी गारंटी दे दी गई तो पूरी उपज को किसानों से खरीद कर उसके भंडारण एवं वितरण की होगी चुनौती

कृषि सुधार कानून आए और चले गए, लेकिन किसानों की चिंता का मुख्य मुद्दा जस का तस है। बीज, खाद, कीटनाशक, बिजली, पानी और मजदूरी की बढ़ती दरों की वजह से खेती की लागत लगातार बढ़ रही है। इसलिए किसान अपनी उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी चाहते हैं। एमएसपी की वर्तमान व्यवस्था अबल तो सभी राज्यों और सभी फसलों पर लागू नहीं है तिस पर यह सरकारों की इच्छा पर निर्भर है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के किसानों को इस व्यवस्था से खूब फायदा हुआ है। वहीं बिहार जैसे राज्यों को न इसके होते हुए लाभ मिल रहा था और न ही इसके हटाए जाने से कोई लाभ हुआ है। इसकी एक मुख्य वजह शायद बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जोतों का बहुत छोटा होना है। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार पंजाब और हरियाणा के किसानों के पास औसतन १४ और ११ बीघा जमीन है वहीं बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों के पास औसत जोत मात्र डेढ़ से तीन बीघा। इसीलिए पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के औसत किसानों के पास बेचने के लिए कम उपज ही बचती है और वे खरीदार की सौदेबाजी का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में एमएसपी की कानूनी गारंटी मिलने से छोटी जोत वाले किसानों को भी शायद इसका कुछ लाभ मिले। कृषि उपज का न्यूनतम मूल्य तय किया जाना कोई नई बात नहीं है। अमेरिका और यूरोप में कृषि उपज के बाजार मूल्यों में गिरावट थामने के लिए किसानों को अपने कुछ खेतों को खाली रखने और जैव-विविधता को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी दी जाती है। भारत में किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए एमएसपी की व्यवस्था है। स्वरूप भिन्न होने के बावजूद बात वही है। हालांकि भारत सरकार को भय है कि एमएसपी की गारंटी से महंगाई बढ़ सकती है, क्योंकि गेहूँ, मक्का और धान जैसी फसलों के एमएसपी उनकी अंतरराष्ट्रीय जिंस बाजार कीमतों के बराबर आ चुके हैं। इसलिए उपज की गुणवत्ता और किसानों की उत्पादकता में गिरावट आने का भी खतरा है। सरकार की

सबसे बड़ी चिंता पूरे देश की उपज का एमएसपी तय करने और उस पर आने वाले खर्च की है। वहीं कुछ कृषि अर्थशास्त्रियों की दलील है कि सरकारी बजट पर इससे कुछ हज़ार करोड़ का ही अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। यह दलील मान भी ली जाए तब भी देश भर की उपज को किसानों से खरीद कर उसके भंडारण और वितरण की चुनौती बहुत बड़ी है। दुनिया भर की सरकारें इसमें नाकाम रही हैं। उसमें उपज के भारी मात्र में बर्बाद होने और घूसखोरी की गुंजाइश बनी रहती है। सरकारों को केवल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा लायक कृषि उपज को खरीदना और उसका भंडारण करना चाहिए। बाकी काम बाजारों पर छोड़कर नीतियों द्वारा मूल्यों पर नियंत्रण रखना चाहिए। जिस तरह गन्ना और कपास किसानों को उनकी फसलों का न्यूनतम मूल्य दिलाया जाता है उसी तरह बाकी फसलों के न्यूनतम मूल्य को व्यापारियों से दिलाने की व्यवस्था क्यों नहीं की जा सकती? यह संभव है, परंतु इसके लिए ग्रामीण इलाकों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का तेजी से विकास करना होगा। घरेलू उपभोक्ता के साथ-साथ यदि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी कृषि उपज की मांग करने लगेगा तो बाजार में उसकी कीमतें स्थिर रखने में आसानी होगी। इस उद्योग को कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए बड़ी संख्या में शीत-गोदामों की जरूरत होगी। उनके खिलाफ किसान नेताओं और उनके समर्थकों ने एक अनुचित मुहिम छेड़ी हुई है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का तेज विकास इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि भारत का कृषि क्षेत्र विकास दर में सेवा और उद्योग जैसे दूसरे क्षेत्रों की तुलना में लगातार पिछड़ रहा है। देश की आधे से अधिक आबादी के कृषि में संलग्न होने के बावजूद आज अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान मात्र १८ प्रतिशत रह गया है। भारत में करीब १४ करोड़ लोगों के पास खेती की जमीन है। उनमें केवल छह करोड़ लोग ही उस पर साल में दो फसलें लेते हैं। उनमें से भी ८० प्रतिशत के पास औसतन तीन बीघा से कम जमीन है। उन्हें गुजर-बसर के लिए खेती से इतर आय के दूसरे साधनों की भी जरूरत है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का विकास ऐसे साधन

उपलब्ध करा सकता है। कृषि क्षेत्र का विकास गांवों और शहरों के बीच बढ़ती आर्थिक विषमता की खाई को पाटने के लिए भी जरूरी है। यह कृषि सुधारों के बिना संभव नहीं। इसके लिए एक नई कृषि क्रांति की जरूरत है। मिट्टी और सिंचाई का वैज्ञानिक प्रबंधन, नकदी फसलों को बढ़ावा, अच्छे बीज सुलभ कराना, बागवानी, वानिकी और मत्स्य पालन को प्रोत्साहन और नई पर्यावरण हितैषी तकनीकों का विकास समय की जरूरत बन चुका है। स्वाभाविक है कि सरकार सारे काम खुद नहीं कर सकती। उनकी पूर्ति के लिए निजी उद्यमों और पूंजी के लिए राह खोलनी होगी। राजनीतिक बिरादरी को उद्यम विरोधी बयानबाजी से भी बाज आना होगा। कृषि जैसे समाज के आधारभूत क्षेत्र को पीछे छोड़कर देश का संतुलित और समावेशी विकास नहीं किया जा सकता। इसके लिए कृषि सुधारों के साथ-साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास जरूरी है। साथ ही किसानों के लिए एमएसपी और उससे भी बढ़कर खेतिहर मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी की गारंटी आवश्यक है, क्योंकि एमएसपी गारंटी से बढ़ने वाली खाद्य पदार्थों की महंगाई की सबसे बड़ी मार उन्हीं खेतिहर और गरीब मजदूरों पर ही पड़ने वाली है। इसलिए एमएसपी गारंटी के बदले किसानों से न्यूनतम मजदूरी की गारंटी और जलवायु की रक्षा के लिए पराली जलाने जैसे प्रदूषणकारी काम न करने और खेती में जलवायु की रक्षा का ध्यान रखने का वचन लेना आवश्यक होगा। एमएसपी गारंटी का मामला कृषि उत्पादकों और उपभोक्ताओं की जरूरतों के बीच संतुलन बिठाने पर भी आधारित है। सरकार को किसानों की आय सुरक्षा के साथ-साथ उपभोक्ताओं की आमराय और सहमति भी जुटानी होगी। कोई लोकतांत्रिक सरकार केवल एक वर्ग की खुशामद कर अधिक दिनों तक नहीं टिक सकती। उपभोक्ताओं का वर्ग किसानों से भी कई गुना बड़ा है। इसलिए समर्थन मूल्य गारंटी जैसी नीति पर आगे बढ़ने से पहले सरकार को उनका ध्यान भी रखना होगा।

बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस



जगदीश चन्द्र बोस एक वैज्ञानिक होने के साथ भौतिक शास्त्री, लेखक और वनस्पति विज्ञानी थे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री बोस का ३० नवम्बर को जन्मदिन है तो आइए हम आपको उनके जीवन के बारे में कुछ रोचक बातें बताते हैं। भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने रेडियो और माइक्रोवेव ऑप्टिक्स के अविष्कार के साथ पेड़-पौधों के जीवन पर भी बहुत सी खोज की। वह भौतिक वैज्ञानिक होने के साथ-साथ जीव वैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक, पुरातत्वविद और लेखक भी थे। रेडियो विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके कार्य को देखते हुए 'इंस्टिट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर' ने उन्हें रेडियो वैज्ञानिक जनकों में से एक माना। जेसी बोस की खोज का नतीजा है कि आज हम रेडियो, टेलीविजन, भुतलीय संचार रिमोट सेन्सिंग, रडार, माइक्रोवेव अवन और इंटरनेट का उपभोग कर रहे हैं। जगदीश चन्द्र बोस का जन्म ३० नवम्बर, १८५८ को मेमनसिंह के ररौली गांव में हुआ था जो वर्तमान में बांग्लादेश में मौजूद है। उनके पिता का नाम भगवान चन्द्र बोस था जो ब्रिटिश इंडिया

गवर्नमेंट में विभिन्न कार्यकारी पदों पर कार्यरत थे। जगदीश चन्द्र के जन्म के समय उनके पिता फरीदपुर के उप मजिस्ट्रेट थे। उनका बचपन फरीदपुर में ही बीता था। साथ ही उनकी प्रारम्भिक शिक्षा भी वहीं पर हुई थी। उन्होंने अपनी प्रारम्भिक शिक्षा गांव की एक पाठशाला से शुरू की क्योंकि उनके पिता चाहते थे कि जगदीश चन्द्र अपनी मातृभाषा सीखी और संस्कृत का ज्ञान अर्जित करें। इसलिए अंग्रेजी स्कूल पास होने के बावजूद भी उनके पिता ने अपने बेटे को सामान्य सी पाठशाला में भेजा।

उसके बाद वर्ष १८६९ में उनको कोलकाता भेजा गया जहां वह कुछ दिनों बाद सेंट जेवियर स्कूल में पढ़े। कुछ दिनों बाद उन्होंने १८७९ में कलकत्ता विश्वविद्यालय से भौतिक-विज्ञान में स्नातक किया। उसके बाद चिकित्साशास्त्र की पढ़ाई करने के लिए वह लंदन गए। लेकिन सेहत खराब होने के कारण वह लंदन से कैम्ब्रिज चले गए और वहां उन्होंने क्राइस्ट कॉलेज में पढ़ाई की। जगदीश चंद्र बोस वर्ष १८८५ में भारत लौटे और सहायक प्राचार्य के रूप में प्रेसीडेंसी कॉलेज में काम किया। यहां उन्होंने १९१५ तक कार्य किया लेकिन उनके साथ

अंग्रेज भेदभाव करते थे। उन्हें अंग्रेज शिक्षकों की तुलना में एक तिहाई वेतन मिलता था। इसका उन्होंने तीन साल तक विरोध करते हुए आर्थिक तंगी झेली। उसके बाद चौथे साल जगदीश चंद्र बोस की जीत हुई और उन्हें पूरी सैलरी दी गयी। बोस एक बहुत अच्छे शिक्षक भी थे और उनके कुछ छात्र सत्येंद्रनाथ बोस प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री भी बने। प्रेसिडेंसी कॉलेज से रिटायर होने के बाद १९१७ ई. में इन्होंने बोस रिसर्च इंस्टिट्यूट, कलकत्ता की स्थापना की और १९३७ तक इसके डायरेक्टर पद पर कार्यरत रहे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी जगदीश चन्द्र बोस को जीवन भर कई प्रकार के पुरस्कार तथा सम्मान प्राप्त हुए। उन्हें १८९६ में लंदन विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि मिली। उसके बाद १९२० में रॉयल सोसायटी के फेलो चुने गए। इंस्टिट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स ने जगदीश चन्द्र बोस को अपने 'वायरलेस हॉल ऑफ फेम' में सम्मिलित किया गया। उसके बाद १९०३ में ब्रिटिश सरकार ने बोस को कम्पेनियन ऑफ दि आर्डर आफ दि इंडियन एम्पायर से सम्मानित किया। १९१७ में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नाइट बैचलर की उपाधि भी प्रदान की।

भारत में गरीबी खत्म करने के वादे अब तक खोखले ही साबित हुए हैं

भारत में गरीबों की हालत कितनी शर्मनाक है। आजादी के ७४ वर्षों में भारत में अमीरी तो बढ़ी है लेकिन वह मुट्ठी भर लोगों

रंगराजन आयोग का मानना था कि गांवों में जिसे ९७२ रु. और शहरों में जिसे १४०७ रु. प्रति माह से ज्यादा मिलते हैं, वह गरीबी

पाएगी। दूसरे शब्दों में व्यक्तिगत आमदनी के साथ-साथ जब तक पर्याप्त राजकीय सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी, नागरिक लोग



और मुट्ठी भर जिलों तक ही पहुंची है। आज भी भारत में गरीबों की संख्या दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा है। हमारे देश के कई जिले ऐसे हैं, जिनमें आधे से ज्यादा लोगों को पेट भर रोटी भी नहीं मिलती। वे

रेखा से ऊपर है। वाह क्या बात है? यदि इन आंकड़ों को रोजाना आमदनी के हिसाब से देखें तो ३० रु. और ५० रु. रोज भी नहीं बनते हैं। इतने रुपए रोज में आज किसी गाय या भैंस को पालना भी मुश्किल है। दूसरे

संतोष और सम्मान का जीवन नहीं जी सकेंगे। सभी सरकारें ये सब सुविधाएं बांटने का काम भी करती रहती हैं। उनका मुख्य लक्ष्य तो इन सुविधाओं की आड़ में वोट बटोरना ही होता है लेकिन जब तक भारत में बौद्धिक श्रम और शारीरिक श्रम का भेदभाव नहीं घटेगा, यहां गरीबी खत्म ठोकती रहेगी। शिक्षा और चिकित्सा, ये दो क्षेत्र ऐसे हैं, जो नागरिकों के मष्तिष्क और शरीर को सबल बनाते हैं। जब तक ये सबको सहज और मुफ्त न मिलें, हमारा देश कभी भी सबल, संपन्न और समतामूलक नहीं बन सकता। ऊपर दिए गए आंकड़ों के आधार

पर आज भी आधे से ज्यादा बिहार, एक-तिहाई से ज्यादा झारखंड और उप्र तथा लगभग १/३ म.प्र. और मेघालय गरीबी में डूबे हुए हैं। यदि विश्व गरीबी मापन संस्था के मानदंडों पर हम पूरे भारत को कसें तो हमें मालूम पड़ेगा कि भारत के १४० करोड़



दवा के अभाव में ही दम तोड़ देते हैं। वे क ख ग भी न लिख सकते हैं न पढ़ सकते हैं। मैंने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ आदिवासी जिलों में लोगों को नग्न और अर्ध-नग्न अवस्था में घूमते हुए भी देखा है।

शब्दों में भारत के गरीब की जिंदगी पशुओं से भी बदतर है। विश्व भर के १९३ देशों वाली गरीबी नापने वाली संस्था का कहना है कि यदि गरीबों की आमदनी इससे भी ज्यादा हो जाए तो भी उसने जो १२ मानदंड बनाए हैं, उनके हिसाब से वे गरीब ही माने जाएंगे,



क्योंकि कोरी बढ़ी हुई आमदनी उन्हें न तो पर्याप्त स्वास्थ्य-सुविधा, शिक्षा, सफाई, भोजन, स्वच्छ पानी, बिजली, घर आदि मुहय्या करवा पाएगी और न ही उन्हें एक सभ्य इंसान की जिंदगी जीने का मौका दे

लोगों में से लगभग १०० करोड़ लोग वंचितों, गरीबों, कमजोरों और जरूरतमंदों की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। पता नहीं, इतने लोगों का उद्धार कैसे होगा और कौन करेगा?

इन घरेलू उपचारों को अपनाकर अस्थमा के मरीज करें अपना बचाव

सर्दियों की शुरुआत होते ही कई लोगों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। जहां कुछ लोग सर्दी-जुकाम के शिकार हो जाते हैं तो वहीं कुछ लोगों का पुराना सा पुराना चोट का दर्द उठ जाता है। जबकि अस्थमा के रोगियों के लिए तो यह सर्दी एक आफत बन जाती है। सर्दियों में अस्थमा रोगियों के लिए अटैक का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उन्हें सांस लेने में दिक्कत और खासी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सर्दियों में बदलते मौसम और सूखी हवा के कारण अस्थमा की समस्या बढ़ जाती है। इस दौरान शुष्क और ठंडी हवा के कारण मांसपेशियों में भी ऐंठन पैदा होने लगती है। चिकित्सकों के अनुसार सर्दियों में अस्थमा रोगी के सांस की नली में सूजन आ जाती है, इसलिए उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है। शोधकर्ताओं ने बताया है कि सर्दी का मौसम अस्थमा के मरीजों के लिए

अच्छा नहीं होता है। इस दौरान उन्हें अस्थमा को नियंत्रण में रखने के लिए कुछ उपाय और अपना खास ख्याल रखना चाहिए। आज हम आपको अस्थमा (दमा) के प्रकार और इसके सर्दियों में बढ़ने वाली समस्या को कम करने के उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, आइए जानते हैं...

आपको बता दें कि अस्थमा या दमा २ प्रकार के होते हैं। पहला- बाहरी अस्थमा और दूसरा- आंतरिक अस्थमा होता है। बाहरी अस्थमा होने का कारण बाहरी एलर्जी है, जैसे- पालतू जानवरों के बाल, धूल के कण और घर में जमी फफूंद आदि। वहीं, आंतरिक अस्थमा होने का कारण हमारे द्वारा ली गई घातक केमिकल तत्वों वाली सांस होती है। जैसे- स्मोकिंग का धुआं, प्रदूषण की हवा और किसी चीज के जलने का धुआं।

सर्दियों में अस्थमा को नियंत्रण में रखने के लिए अपनाएं यह उपाय- बार-बार हाथ धोएं अपने हाथों को बार-बार साबुन और पानी से जरूर धोएं। इस तरह से कीटाणुओं के फैलने की संभावना को कम किया जा सकता है। आप चाहें तो हैंड सेनिटाइजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने घर के बच्चों और अन्य सदस्यों को भी हाथ धोने के लिए कहें, इससे घर

के लिए खतरनाक हो सकता है। घर में ही करें एक्सरसाइज सर्दियों में बहुत कम तापमान और खूब ठंडी हवा चलना आम बात है। ऐसे में अस्थमा रोगियों के लिए घर में ही रहना सही है। अगर आप अस्थमा मरीज हैं और एक्सरसाइज या योग करने के लिए जिम या पार्क में जाते हैं तो आपको बता दें कि ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए सर्दियों में घर में ही एक्सरसाइज करें।

अस्थमा का घरेलू उपचार - हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें, आपके लिए पालक और गाजर का रस फायदेमंद रहेगा। - अदरक, लहसुन, काली मिर्च और हल्दी को अपने आहार में जरूर शामिल करें, यह सर्दियों में अस्थमा से लड़ने में मदद करते हैं।



में फैलने से बचाव हो सकेगा।

मुंह बंद रखें

अगर आप अस्थमा रोगी हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप अपने मुंह पर मास्क या कपड़ा लगाएं। मुंह को बंद रखना फेफड़ों के लिए काफी अच्छा रहता है। हमारी नाक में इतनी क्षमता होती है कि वो सांस लेने वाली हवा को फेफड़ों में गर्माहट दे सकती है।

आग वाली जगह पर बैठने से बचें भले ही आग के पास बैठकर सर्दियों में गर्माहट मिलती हो लेकिन अस्थमा रोगियों के लिए ये काफी घातक साबित हो सकती हैं। शोध में पाया गया है कि अस्थमा के रोगियों के लिए जलता हुआ तंबाकू और लकड़ी एक जैसा ही होता है। आग से आने वाले धुएं से फेफड़ों में परेशानी हो सकती है। यह अस्थमा मरीजों

के लिए खतरनाक हो सकता है।

घर में ही करें एक्सरसाइज सर्दियों में बहुत कम तापमान और खूब ठंडी हवा चलना आम बात है। ऐसे में अस्थमा रोगियों के लिए घर में ही रहना सही है। अगर आप अस्थमा मरीज हैं और एक्सरसाइज या योग करने के लिए जिम या पार्क में जाते हैं तो आपको बता दें कि ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए सर्दियों में घर में ही एक्सरसाइज करें।

अस्थमा का घरेलू उपचार

- हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें, आपके लिए पालक और गाजर का रस फायदेमंद रहेगा।

- अदरक, लहसुन, काली मिर्च और हल्दी को अपने आहार में जरूर शामिल करें, यह सर्दियों में अस्थमा से लड़ने में मदद करते हैं।

- आपको पुराने चावल, कुल्थी की दाल, गेहूं, जौ, मूंग और पटोल का सेवन करना चाहिए।

- गुनगुने पानी का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें, ये सर्दियों में आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा।

- अस्थमा रोगियों को शहद का सेवन करना चाहिए।

इन बातों का रखें ख्याल

- बाहर का खाना न खाएं।
- धूम्रपान वाले स्थान पर न खड़े हों।
- घर से निकलते समय मास्क या स्कार्फ जरूर लगाएं।

- सर्दियों में ज्यादा भीड़भाड़ और प्रदूषण वाले जगहों पर जाने से बचें।

- सर्दियों में संतरे, चुकंदर, नींबू, पालक और मसूर की दाल का ज्यादा सेवन करें।

खाने में टमाटर की जगह इस्तेमाल की जा सकती हैं ये चीजें



बेमौसम बारिश और कम आपूर्ति के कारण कई जगहों पर टमाटर के दाम तीन गुना बढ़ गए हैं, जिसके कारण आम आदमी की थाली से यह गायब होता जा रहा है और सब्जियों का स्वाद भी कम हो रहा है। हालांकि, आप चाहें बिना टमाटर के भी अपने खाने का स्वाद बढ़ा सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं, जिनका इस्तेमाल आप अपने खाने में टमाटर की जगह कर सकते हैं।

इमली

बढ़ते दाम के कारण अगर आप टमाटर नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप इसकी जगह अपने खाने में इमली का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ी सी इमली को पानी में डालें और जब आप सब्जी या चटनी बनाने जा रहे हों तो उससे पहले इमली के पानी की इमली को हाथ से तब तक मलें, जब तक कि उसका बीज बाहर न आ जाए। अब इमली

के पानी को छानकर सब्जी की ग्रेवी या फिर चटनी में मिलाएं।

टोमेटो सॉस

अगर आपके घर में टोमेटो सॉस है तो आप इसका इस्तेमाल भी टमाटर की जगह खाने में कर सकते हैं। जब आपको किसी खाने में थोड़े मिठास वाले स्वाद के लिए टमाटर की जरूरत हो तो आप टोमेटो सॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए पनीर की सब्जी बनाते समय टोमेटो सॉस डाली जा सकता है। वहीं, जिन व्यंजनों में आपको तीखापन और टमाटर का रंग चाहिए वहां आप चिली सॉस के साथ टोमेटो सॉस डाल सकते हैं।

कढ़ू

कढ़ू एक ऐसी सब्जी है, जिसमें टमाटर की तरह मिठास और गाढ़ापन होता है यानी जिन व्यंजनों को बनाते समय आप गाढ़ापन लाने के लिए टमाटर की प्यूरी का इस्तेमाल

करते हैं वहां आप कढ़ू से प्यूरी बनाकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कढ़ू की प्यूरी बनाने के लिए आपको बस कढ़ू को छिलें, फिर उसे मिक्सी में पीसकर इस्तेमाल करें। इसके अतिरिक्त, आप जहां-जहां टमाटर को बारीक काटकर मिलाते थे, वहां आप कढ़ू को काटकर भी मिला सकते हैं।

अमचूर और सिरका

चटनी हो या फिर चटनी, जिन चीजों को बनाते समय आपको टमाटर का खट्टापन चाहिए वहां आप टमाटर की जगह अमचूर या फिर सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि, इनका इस्तेमाल करते वक्त ध्यान रखें कि इन्हें अधिक मात्रा में चीजों में नहीं डालना है, नहीं तो ये ज्यादा खट्टा बनाकर सब्जी का स्वाद भी बिगाड़ सकते हैं। अमचूर और सिरके के अलावा, दही और आंवले के पाउडर का इस्तेमाल करके भी खाने में खट्टापन लाया जा सकता है।

بیٹیوں کی حفاظت کیجئے: ایک فکری مطالعہ

عین الحق امینی قاسمی

میں بتلایا گیا ہے کہ: روئے زمین پر انسان نظام فطرت کا عظیم شاہکار ہے، اور اس شاہکار کا خوبصورت نمونہ عورت ہے۔ زندگی کی تعمیر کا بنیادی اصول ہے کہ انسان فطرت کے نظام کے مطابق زندگی گزارے، اسی میں کامیابی ہے اور اس نظام سے انحراف کا نام ناکامی ہے۔ دین اسلام دراصل دین انسان ہے، جو فطرت کے نظام پر مبنی ہے، جہاں ہر فرد کا دائرہ کار اور حدود متعین ہیں، انسان جب تک اس باؤنڈری میں رہتا ہے، یہ صحیح سمت میں رہتا ہے، اور جیسے ہی حدود سے تجاوز کرتا ہے شیطان بن جاتا ہے، فساد و بگاڑ اور بے

چینی شروع ہو جاتی ہے ”اسی طرح ”شدھی تحریک“ کے قیام کی خطرناکیوں کا ذکر کرتے ہوئے مؤلف نے انتہائی درد و کرب کے ساتھ لکھا ہے کہ: شدھی تحریک کے موقع پر چند اہل اللہ اور جو اس سال علماء کی فعال ٹیم نے دعوت و تبلیغ اور ذہن سازی اس موثر انداز سے کی کہ ارتداد کی لہر تھم گئی اور ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو منہ کی کھانی پڑی، آج پھر یہ طوفان بلا خیز ہمارے گھروں کا رخ کر چکا ہے، اس سے قبل کہ یہ سونامی کی شکل اختیار کر لے، ہمیں خواہید ملت کو بیدار کرنا ہوگا اور انہیں اپنے گھر کا چوکیدار



بنانا ہوگا، تاکہ ایمان کا لئیر اپنے منصوبے میں کامیاب نہ ہو سکے ”کتابچے میں مذکور عناوین و مواد بلاشبہ قاری کے لئے کشش اور معلومات میں اضافے کا سامان ہے، یہی وجہ ہے کہ کتابچہ ہاتھ میں لینے کے بعد مکمل کرنے سے پہلے تک تشنگی کا احساس زندہ رہتا ہے، ذیل میں پہلے ایک بار ذکر شدہ چند اہم عناوین پر ایک نظر ڈال لیجئے! ”بیٹیوں کا تحفظ سلگتا موضوع۔ ارتداد کی آندھی۔ پونم پانڈے کی رپورٹ۔ کیوں بھاگ رہی ہیں بیٹیاں۔ برائیاں کی پیدائش پر قدغن۔ انٹرنیٹ کی خاص برائیاں۔ تہواروں کے موقع پر بھی رہے نگاہ۔ بوائے فرینڈ سے شادی یا کوٹ میرج۔ بین مذاہب شادی کے قانونی داؤ پیچ۔ اغیار میں شادی کے بھیانک انجام۔ شادی میں تاخیر کے نقصانات وغیرہ“ اسی طرح کتابچے کے آخری حصے میں خوبیوں کے ساتھ مثالی خواتین اسلام کے روح افزاء واقعات کو ذکر کرتے ہوئے ملک بھر کی دینی، ملی تنظیموں، سنجیدہ سماجی کاروں اور ائمہ و اساتذہ کو بے طور ایک ذمہ دار فرادہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس بھی کرایا ہے۔ کتاب دیدہ زیب بھی ہے اور عمدہ کاغذ و طباعت سے آراستہ بھی، کتاب پر قیمت درج نہیں ہے، البتہ امارت شرعیہ پھلواری شریف پٹنہ کے شعبہ نشر و اشاعت سے شائع ہوئی ہے، بالغ نظری سے پروف ریڈنگ کی خدمت انجام دی ہوئی ہے، اس لئے پوری تحریر پڑھتے ہوئے کہیں بھی تعب و تھکن کا ذرا بھی احساس نہیں ہوتا۔

تاریخ گواہ ہے کہ امارت شرعیہ پھلواری شریف پٹنہ کے بانی قائد ملت، مفکر اسلام حضرت مولانا ابوالحسن سید محمد سجاد علیہ الرحمہ شدھی تحریکوں کو کچلنے اور اس کی ناکہ بندی کے لئے پوری زندگی محاذ آرائی کرتے رہے، آپ کے بعد بھی امارت شرعیہ سے وابستہ تمام امرائے شریعت اور وہاں کے خدام، دعوت و تبلیغ کے اس سلسلے کو جاری رکھنے

اور ملت اسلامیہ کو کفر و ارتداد سے بچانے کے لئے ہمیشہ میدان جہاد میں باطل کو لاکارنے اور اس سے لوہا لینے کا کام کرتے رہے ہیں، جس کے نتیجے میں صوبہ ”بہار“ کی زمین پر پوری قوت کے ساتھ فتنوں کی سرکوبی ہوتی رہی اور باطل کھلم کھلا سر اٹھانے کی جرئت نہ کر سکا۔ الحمد للہ یہ سلسلہ آج بھی پورے احساس جواب دہی کے ساتھ جاری ہے، چنانچہ ”بیٹیوں کی حفاظت کیجئے“ اسی سمت میں خواہید ملت کو جگانے اور بیٹیوں کو ارتداد سے بچانے کی عظیم کوشش ہے۔

چنانچہ زیر مطالعہ کتاب ”خالص“ طبقہ نسواں ” بالخصوص بیٹیوں کی مثبت رہنمائی اور ان کے ایمانی و اخلاقی تحفظ کے جذبے سے لکھی گئی ہے، کتاب میں سطر سطر سے بیٹیوں کو صالح فکر اور اسلامی اخلاق و اقدار کی دعوت دی گئی ہے، کتاب کے مؤلف، نائب امیر شریعت امارت شرعیہ پھلواری شریف پٹنہ ہیں، خوبی کی بات یہ ہے محترم مولانا محمد شمشاد رحمانی قاسمی صاحب دارالعلوم وقف دیوبند کے بافیض استاذ حدیث بھی ہیں۔ کتاب کے مطالعے سے موصوف کی نہ صرف وسیع نظری صاف جھلک رہی ہے، بلکہ سماج و معاشرے کی تازہ صورت حال سے بھی ان کی گہری بصیرت کا اندازہ ہوتا ہے، اصلاحی جذبات اور اکابرین امارت شرعیہ کے پاکیزہ افکار و خیالات، مؤلف موصوف کے قلم سے صاف عیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں کم وقت میں شہرت و مقبولیت دی ہے، وہ اس وقت ملک بھر میں اپنے اکابرین بالخصوص مفکر اسلام امیر شریعت صالح حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمہ اللہ کے پرتو ہیں۔

باون صفحات پر مشتمل یہ کتابچہ، صفحہ بارہ سے اپنے اصل مضمون کے ساتھ باضابطہ شروع ہوا ہے، اس سے پہلے کے صفحات میں ترجمان امارت شرعیہ ہفت روزہ نقیب کے ایڈیٹر مفتی محمد ثناء الہدی قاسمی صاحب کا دل کو اپیل کرنے والا ایک پرائز مقدمہ بھی شامل کتاب ہے۔ کتاب میں خواتین کے مقام و مرتبہ کو تاریخی پس منظر میں تقابلی کرنے کے بعد اسلام کے دینے ہوئے حقوق کو سب سے عظیم تر قرار دیا گیا ہے اور معرضی لہجے

وقف املاک کو غیر قانونی قبضہ سے آزاد کرانے کا عزم

میں غیروں کے ساتھ اپنے بھی کہیں سے بھی پیچھے نہیں۔ نیز گھٹم پور، بارہ بنکی، ودیگر کنی واقعات مساجد و مدارس اور قبرستانوں کی حفاظت کے لیے جلد از جلد اہم اقدامات کا پیغام دیتے ہیں۔ جس کے لیے وقف ویلفیئر فورم کی کوشش لائق تحریف ہے۔ لوگوں کو اس مہم سے جڑ کر بیداری کے ساتھ جتنی جلدی ہو سکے اپنے مدارس، مساجد اور قبرستانوں کے ضروری دستاویزات مضبوط بنانے کے ساتھ وقف میں اندراج یقینی بنانا چاہیے۔ سابق چیف ایگزیکٹو افسر سنی سینٹرل وقف بورڈ ڈاکٹر شمیم احمد نے بتایا کہ وقف املاک کی حفاظت کیلئے ہر ضلع میں، ضلع ججسٹریٹ، اسسٹنٹ کمشنر اور ڈی ایم و آپ کی بھرپور مدد کر سکتے ہیں۔ جس کے لیے بیداری اور جدوجہد جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ سابق آئی آر ایس اکرام الجبار خان نے صدارتی خطاب میں وقف املاک پر تفصیلی روشنی ڈالنے کے ساتھ اس کے تحفظ کے لیے مفید مشوروں سے نوازا۔ سمینار میں نظامت کی ذمہ داری محمد خالد نے بحسن و خوبی نبھائی۔ اس موقع پر محمد سلیمان، چودھری ریاض الدین صدیقی، ایڈووکیٹ عبدالحی خان، ایڈووکیٹ ایاز احمد، جاوید احمد سمیت بڑی تعداد میں مسلم دانشوران موجود تھے۔

جس پر لوگ کہیں سے بھی رابطہ کر کے اپنی شکایت درج کرانے کے ساتھ وقف سے متعلق ضروری معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ وقف املاک کو غیر قانونی قبضوں سے آزاد کرانے کے طریق کار سے متعلق سوال پر انہوں نے بتایا کہ وقف ترمیمی ایکٹ 2013 کافی مضبوط اور معاون ہے، لیکن عام طور پر لوگوں کو اس کی جانکاری اور بیداری نہ ہونے کی وجہ سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں۔ اس ترمیمی ایکٹ کے تحت ٹی ٹی ایکٹ کا استعمال کر کے وقف املاک کو غیر قانونی قبضے سے آزاد کرانے کے ساتھ راشی مافیا پر مقدمات بھی درج کرائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مدارس مساجد اور قبرستانوں کی حفاظت کے لیے وقف میں رجسٹریشن اور تحفظ کے قوانین کی جانکاری وقت کی اہم ضرورت ہے۔ وقف ویلفیئر فورم کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کو مساجد مدارس اور قبرستانوں کی زمینوں کو وقف بورڈ میں درج کرانے کے تئیں بیدار کیا جائے نیز ضلع سطح پر گرماں کمیٹی تشکیل دے کر لوگوں کی رہنمائی وقف املاک کی حفاظت کے تئیں بیدار کیا جائے۔ قاضی شہر حافظ عبدالقدوس ہادی نے کہا کہ شہروں و اطراف میں وقف املاک پر غیر قانونی قبضہ کے مسائل انتہائی تشویشناک ہے۔ جس

شکیل رشید

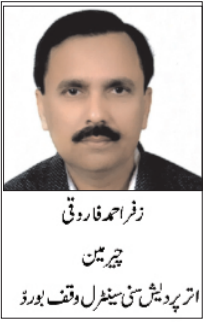
منور فاروقی کا ایک اسٹیٹڈ آپ کامیڈین کی حیثیت سے اپنے فن کے مظاہرے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینے کا اعلان ہمارے ملک ہندوستان میں 'جمہوریت' کی ناکامی کی ایک جھپتی جاگتی مثال ہے۔ ۲۹ سالہ منور فاروقی اور اسے نشانہ بنانے والے عناصر اس ملک کی دو ایسی سمتوں کی علامت بن گئے ہیں جن میں سے ایک جمہوری حقوق کے لیے ہر حالت میں جدوجہد کرنے والوں کی طرف جاتی ہے، اور دوسری جمہوری حقوق کو لوگوں سے زور اور جبر سے چھین لینے کے لیے ہر طرح کی فوج حرکتوں جتنی کہ تشدد کرنے کی جانب جاتی ہے۔ گذشتہ دنوں منور فاروقی کا ایک ٹوئٹ آیا تھا جس میں اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اسٹیٹڈ آپ کامیڈی کو چھوڑ دینے کا اعلان کیا تھا۔ اتوار کے روز بنگلور کے 'گڈ شیفرڈ آڈیو ٹیم' میں 'کرنن کال' نامی ایک گروپ نے منور فاروقی کا ایک پروگرام رکھا تھا جسے ڈنگری ٹونو و ہیر' کا نام دیا گیا تھا۔ اتوار کو جب پروگرام ہوا تھا، منتظمین کو اشوک نگر علاقہ کی پولس کی طرف سے یہ مشورہ دیا گیا کہ وہ پروگرام کو ملتوی کر دیں کیونکہ انہیں یہ اطلاع ملی ہے کہ منور فاروقی کے شو کے خلاف کچھ تنظیمیں بڑے پیمانے پر احتجاج کر سکتی ہیں۔ یہ مشورہ ایک طرح سے پولس کا 'حکم' ہی تھا۔ منتظمین کو 'مشورہ' یا 'حکم' پر عمل کرتے ہوئے منور فاروقی کے شو کو ملتوی کرنا پڑا۔ شو ملتوی ہونے کے بعد منور فاروقی کا شوکل میڈیا پر اعلان آیا کہ اب بہت ہو گیا، وہ اب اسٹیٹڈ آپ کامیڈین کی حیثیت سے کسی بھی شو میں شرکت نہیں کرے گا۔ یہ اعلان کوئی ایک پروگرام کے ملتوی کیے جانے کا نتیجہ نہیں تھا، ادھر چند مہینوں کے دوران منور فاروقی مسلسل 'ہندو تو ادیوں' کے نشانے پر رہا ہے۔ یہ وہی منور فاروقی ہے جسے اس الزام میں کہ اس نے ہندو یودی دیوتاؤں کی 'توپین' کی ہے اندور میں ایک مہینے تک جیل میں رہنا پڑا تھا، حالانکہ اس پر لگا تو 'توپین' کا الزام ثابت نہیں ہو سکا تھا۔ ممبئی، رائے پور، سورت، ودودور اور احمد آباد میں 'ہندو تو ادیوں' نے منور فاروقی کے شو نہیں ہونے دینے، بار بار

اسے نشانہ بنایا۔ بنگلور میں جو پروگرام تھا وہ ایک پرائیویٹ پروگرام تھا، اس کے لئے سپریم کورٹ کی ہدایت کے عین مطابق، کسی بھی طرح کے پولس کی اجازت لینا لازمی نہیں تھا۔ لیکن اسن و اماں کو خطرہ بتا کر پولس نے منتظمین کو اس پروگرام کو ملتوی کرنے پر مجبور کر دیا۔ ایک کمر وادی تنظیم 'ہندو جن جاگرتی سمیٹی' نے بنگلور کے پولس کمشنر کمل پنت کو خط لکھ کر منور فاروقی کے پروگرام کو ملتوی کرنے پر زور ڈالا تھا۔ اس خط کو دھمکی بھرا خط بھی کہا جاسکتا ہے۔ خط میں یہ الزام، جو کہ ثابت نہیں ہو سکا ہے، لگا گیا ہے کہ منور فاروقی ہندو یودی دیوتاؤں کی

معاملہ منور فاروقی کا اور جمہوریت کی ہار

توپین کا مرکز ہوتا ہے۔ خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ شہریت ترمیمی قانون مجریہ ۲۰۲۰ء کے خلاف باتیں کرتا ہے اور گودھرا فسادات کا تذکرہ بھی اس کے شو میں ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا کسی جمہوری ملک میں کوئی کسی کو روک سکتا ہے کہ وہ اپنی زبان پر تلاؤں ڈال کر رکھے اور حق بات بھی نہ بولے؟ گودھرا فساد یا این آر سی اور سی اے اے کے بارے میں باتیں کرنا کب سے جرم ہو گیا ہے؟ سچ یہ ہے کہ منور فاروقی کی ایک 'مسلمان' کی حیثیت ہندو تو ادیوں کو ہضم نہیں ہو رہی ہے، ان کا کہنا ہے کہ کوئی مسلمان کیسے سی اے اے اور فسادات کے خلاف بول سکتا ہے؟ خود منور فاروقی کا کہنا ہے کہ اسے اس لیے پروگرام کرنے سے روکا جا رہا ہے کہ اس کا نام منور فاروقی ہے۔ منور فاروقی کے اسٹیٹڈ آپ کامیڈی چھوڑ دینے کو اس ملک میں جمہوریت کی ہار اور فرقہ پرستی کی جیت کہا جائے گا۔ رائل گاندھی نے ایک ٹوئٹ کر کے منور فاروقی سے گڈ اثرش کی ہے کہ وہ فرقہ پرستی کو کامیاب نہ ہونے دے اور اپنے فن کا مظاہرہ کرتا رہے۔ مزید آوازیں منور فاروقی کے حق میں اٹھ رہی ہیں۔ ضروری ہے کہ ہر کوئی فرقہ پرستی کے خلاف کھڑا ہوتا کہ اس ملک کے جمہوریت دشمن اظہار آزادی کے حق پر ڈال کر نہ ڈال سکیں۔ ضروری ہے کہ ہیکے بنگلور پولس کے خلاف بھی کارروائی کی جائے کہ اس نے گوری لنکیش اور کبرگی جیسے عقلیت پسندوں کو راہ سے ہٹانے والی ہندو جن جاگرتی سمیٹی کے سامنے گھٹنے ٹیک دینے اور اپنے فرض سے کوتاہی کی ہے۔

وقف ٹوڈے جریدے کی اشاعت پر اتر پردیش سنی سینٹرل وقف بورڈ کی جانب سے مبارکباد



زفر احمد فاروقی

چیرمین

اتر پردیش سنی سینٹرل وقف بورڈ

وقف ایکٹ 1995 کے مطابق متولیان و انتظامیہ کمیٹی کے فرائض

دفعہ 36 کے تحت اوقاف کارجریشن

تمام اوقاف خواہ وہ وقف ایکٹ 1995 سے قبل کا ہو یا مابعد، دفتر بورڈ میں درج کیا جائے گا

اوقاف کے رجسٹریشن کی درخواست متولی/انتظامیہ کمیٹی یا اوقاف کے خاندان والے یا مستفید ہونے والے مسلمان شخص کی جانب سے دی جاسکے گی۔

رجسٹریشن کے لئے دفتر بورڈ یا بورڈ کی ویب سائٹ (<https://upsunniwaqfboard.org>) سے حاصل شدہ رجسٹریشن فارم کے ذریعہ قواعد کے مطابق درخواست کی جاسکے گی۔

تمام درخواستیں رجسٹریشن فارم کے ساتھ وقف نامہ کی ایک نقل یا اگر ایسا کوئی وقف نامہ عمل درآمد نہیں کیا گیا ہے یا اس کی نقل حاصل نہیں کی جاسکتی تو اس میں وقف کے وجود اس کے مقاصد کی تمام خصوصیات ہوں گی جہاں تک کہ درخواست گزار کی جانکاری ہو۔

دفعہ 42: وقف کے انتظام میں کی گئی ترمیم کے بارے میں

دفتر بورڈ میں درج وقف کے متولی/انتظامیہ کمیٹی کے ممبران کی وفات یا استعفی دئے جانے یا ہٹائے جانے کی صورت میں نئی انتظامیہ کمیٹی/متولی فوری طور پر بورڈ کو تبدیلی کے بارے میں مطلع کرے گی۔

دفعہ 44 کے تحت بجٹ

وقف کا ہر متولی/انتظامیہ کمیٹی اگلے مالی سال کا بجٹ تیار کر کے 28 فروری تک بورڈ کو بھیجے گی، جس میں اس مالی سال کے دوران تخمینی آمدنی اور اخراجات کی تفصیلات ہوں گی۔

دفعہ 46 کے تحت وقف کے کھاتوں (اکاؤنٹس) کی تفصیلات کے سلسلے میں

ہر وقف کا متولی/انتظامیہ کمیٹی اوقاف کے باقاعدہ اکاؤنٹس کو برقرار رکھے گی اور ہر مالی سال میں موصول اور خرچ کئے گئے مکمل اور درست حساب کتاب تیار کرے گی اور اسے ہر سال 30 جون تک بورڈ میں داخل کرے گی۔

دفعہ 50 کے تحت متولی/انتظامیہ کمیٹیوں کے فرائض

یہ کہ متولی/انتظامیہ کمیٹی بورڈ کی ہدایات پر ایکٹ 1995 کے مطابق عمل درآمد کرے۔

دفتر بورڈ کو وقتاً فوقتاً اس طرح کی معلومات یا تفصیلات فراہم کرنا جو دفتر بورڈ کی جانب سے دریافت کی جائے۔

وقف املاک، اکاؤنٹس یا ریکارڈ اور متعلقہ دستاویزات کا معائنہ کرنے کی اجازت

تمام عوامی واجبات ادا کریں۔

ایسا کوئی عمل کریں جو اس ایکٹ 1995 میں کرنے کی توقع کی گئی ہو۔

دفعہ 72 کے تحت بورڈ کو قابل ادائیگی سالانہ شراکت

ہر وقف کا متولی/انتظامیہ کمیٹی جس کی سالانہ ادائیگی پانچ ہزار سے کم نہ ہو، بورڈ کے قواعد کے مطابق بورڈ کی جانب سے فراہم کی جانے والی خدمات کے لئے بورڈ میں عطیہ کرے گا۔

وقف لیزرولس 2014 (ترمیم شدہ)

کسی بھی وقف جائیداد کو کرایہ اپنہ پر دیتے وقت وقف لیزرولس 2014 (ترمیم شدہ) کی تعمیل کو یقینی بنایا جائے گا۔

علاوہ ازیں وقف املاک پر ناجائز قبضہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے جس کو وقف ایکٹ 1995 کی دفعہ 54 کے تحت ہٹانا یا روکنا ہے جو کہ ایک پیچیدہ اور طویل عمل ہے لہذا ناجائز قبضہ کی

بے دخلی کی فوری کارروائی کے لئے اتر پردیش پبلک پرامیسس (ناجائز قابضین کی بے دخلی) ترمیم شدہ) کا ایکٹ 2014 میں تدارک کیا جا چکا ہے۔

گلدستہ ہدایت نکاح، مہر اور جہیز

محمد اختر عادل گیلانی

اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کی افزائش اور بقا کے لیے آدم اور حوا کی شکل میں دو مخالف صنف کی تخلیق کی اور اس جوڑے کے باہمی تعلق سے بے شمار مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ مرد و عورت کے اس فطری اور جائز تعلق کو شریعت کی زبان میں نکاح کہتے ہیں۔ نسل انسانی کی افزائش اور انسانی تہذیب کی بقا و کامیابی کی بنیادی اور اولین اینٹ نکاح ہے۔ اس کے بغیر نہ کوئی خاندان وجود میں آسکتا ہے اور نہ کسی صالح ساج/معاشرے کا تصور کیا جاسکتا ہے۔ اسلامی نقطہ نگاہ سے نکاح نہ صرف جسمانی و سماجی ضرورت ہے بلکہ اللہ کی نشانی، عبادت، نصف الایمان، فطری ضرورت اور ذہنی و قلبی سکون حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ شرم و حیا، شرافت اور پاکدامنی کا مضبوط قلع ہے۔ نکاح سے نگاہ اور نفس کشمکشوں میں رہنے کے ساتھ ہی آدمی شیطانی ترغیبات اور اس کے نرغے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو زیادہ عرصے تک ازدواجی زندگی سے دور اور محروم رکھنے سے ساج میں گھناؤنی اخلاقی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔

جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو نکاح کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص نکاح کی ذمہ داریاں اٹھانے کی طاقت و استطاعت رکھتا ہو اسے لازماً نکاح کر لینا چاہئے۔ استطاعت سے مراد ہونے والی بیوی کی ضروریات زندگی (لباس، خوراک، مکان اور دوسرے ضروری اخراجات) کو پورا کرنے کی جسمانی و مالی صلاحیت کا ہونا ہے۔ نکاح کے لیے حسب و نسب اور مال و جمال کے بجائے دینداری کو معیار بنانے اور ترجیح دینے کی تاکید فرمائی۔ ان ہدایات کو نظر انداز کر دینے کی وجہ سے مسلم سماج میں طرح طرح کی برائیوں جنم لے رہی اور پروان چڑھ رہی ہیں۔ ہمارے نوجوان اعلیٰ تعلیم،

نوکری، زیادہ کمائی، دولت کی حوس، جہیز کے حرام مال کی لالچ اور سیرت و کردار سے عاری حور پری کی چاہت میں اپنی جوانی کا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلعم نے نکاح کو آسان اور زنا کو مشکل ترین بنایا جس کی ترتیب ہم نے الٹ دی جس کا خمیازہ آج مسلم سماج بھگت رہا ہے۔

مہر: مہر عورت کا حق ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "مخورتوں کا مہر خوشدلی کے ساتھ ادا کرو۔" اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ (بغیر مہر ادا کیے) زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو۔" رسول اللہ صلعم نے اگرچہ مہر کی کوئی مقدار مقرر نہیں فرمائی لیکن عملاً "تھوڑا اور شوہر کی مالی حیثیت کے مطابق مقرر کرنے کی ترغیب فرمائی ہے جسے شوہر باسانی ادا کر سکے۔ آپ صلعم نے یہ بھی فرمایا کہ بہترین مہر وہ ہے جس کا ادا کرنا آسان ہو۔ مہر کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف روپیے یا سونا/چاندی کی شکل میں ہو بلکہ کوئی بھی پسندیدہ اور محبوب چیز مہر ہو سکتی ہے جسے لڑکا اور لڑکی (یا ان کے گارجین) طے کر لیں۔ حتیٰ کہ قرآنی آیات سیکھانا بھی مہر ہو سکتا ہے۔ مہر نکاح کے وقت ہی ادا کر دینا چاہئے۔ حدیث یہ بتلاتی ہے کہ نکاح کے وقت دل میں مہر ادا کرنے کی نیت نہ ہو تو ویسا نکاح، نکاح نہیں بلکہ زنا کاری کا ذریعہ ہوگا۔ البتہ اگر کسی شرعی مجبوری کی بنا پر آپسی اتفاق سے بر وقت مہر ادا نہ کر سکا تو اس کو جلد سے جلد ادا کرنے کی فکر اور کوشش کرنی چاہئے۔ مہر عورت کی ذاتی ملکیت ہے وہ اس میں مالکانہ تصرف کر سکتی ہے۔ بیوی کی اجازت کے بغیر شوہر کو دباؤ ڈال کر یا سختی برت کر مہر میں تصرف کرنے کا اختیار نہیں ہے۔

یہ تو ہوئی شریعت کی باتیں کہ عورت کا مہر ادا کر کے نکاح کرو اور ہاتھ لگاؤ لیکن آج عملاً اس کا ٹھیک لٹا ہوتا اور ہو رہا ہے۔ لڑکا زنا نہ بن کر بے شرمی کے ساتھ پہلے اپنا مہر (جہیز، بھیک) مانگتا اور لیتا ہے

تب نکاح قبول کرتا ہے اور لڑکی کے مہر اور حق کو ادھار کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے۔

چونکہ مہر کو دین (قرض) بنا دیا گیا اور ادا نہ کرنے اور معاف کر لینے کی دل میں نیت ہوتی ہے اس لیے مہر میں موٹی موٹی رقم طے کی جاتی ہیں۔ لوگوں کی نگاہ میں مہر کی کوئی اہمیت اور وقعت نہیں ہے اور نہ نبی صلعم کی سنت کی پرواہ۔ جہاں جوڑے و گھوڑے، میرتج ہال/ہوٹل، سجاوٹ اور بارات و ولیمہ پر لاکھ لاکھ خرچ کیے جاتے ہیں وہاں کیا چند ہزار مہر کے کفد ادا نہیں کیے جاسکتے؟ ہمارے سوچنے اور برتنے کا انداز ہی بدل گیا ہے۔ اب نکاح اور مہر عبادت نہیں تجارت اور لعنت بن گئی ہے۔ اسی تجارت کا دوسرا نام جہیز ہے۔

جہیز: جہیز کے نام پر آج کل مسلم سماج میں جو فرسودہ رسم کا چلن ہے اس کا نہ کوئی جواز ہے اور نہ شرعی بنیاد۔ اس سلسلے میں جہیز فاطمی کا جو حوالہ دیا جاتا ہے اس کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے۔ پچھلے کالم (جہ) 19/ نومبر) میں اس پر تفصیلی روشنی ڈالی جا چکی ہے۔ نکاح کے بعد لڑکی کی ضروریات زندگی کے سامان کو اپنی استطاعت کے مطابق مہیا کرنا لڑکے کی ذمہ داری ہی نہیں بلکہ اس کا فرض ہے۔ شریعت نے اس کی ذمہ داری اور بوجھ لڑکی کے باپ یا سرپرست پر نہیں ڈالا ہے۔ لیکن آج کل عام مسلمان تو دودر رہے بڑے بڑے علماء دین، دین کے داعی اور پیران طریقت بھی جہیز کے معاملے میں پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پاس و لحاظ نہیں رکھتے۔ منبر و محراب سے اس موضوع پر زور دار اور لچھے دار تقریریں کی جاتی ہیں کہ "رسول اللہ صلعم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہیں لیکن نہ سامعین پر اس کا کچھ اثر ہوتا ہے اور نہ علماء دین اور خطیب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق ہوتی ہے۔ یہ سب باتیں زبانی جمع خرچ سے آگے نہیں بڑھ پاتی ہیں۔

☆☆☆

زرعی قوانین کی واپسی کا سبق



معصوم مراد آبادی

آخر کار حکومت کو کسانوں کے آگے جھکنا ہی پڑا۔ ایک سال پہلے پارلیمنٹ سے زور زبردستی پاس کرائے گئے متنازعہ زرعی قوانین کو واپس لینے کا اعلان خود وزیر اعظم نریندر مودی نے کیا۔ انھوں نے جمعہ صبح قوم کے نام خصوصی خطاب میں کہا کہ ”آج میں آپ کو، پورے دیش کو یہ بتانے آیا ہوں کہ ہم نے تینوں زرعی قوانین کو واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس مہینے کے آخر میں شروع ہو رہے پارلیمنٹ کے اجلاس میں ہم ان تینوں قوانین کو واپس لینے کا دستوری عمل پورا کر دیں گے۔“ اس طرح وزیر اعظم نے از خود ان متنازعہ قوانین کو واپس لینے کا اعلان کیا، جنھیں اب تک انھوں نے اپنے وقار کا مسئلہ بنا رکھا تھا۔ اس سے یہی ثابت ہوا کہ جمہوریت میں عوام ہی سب سے اہم ہوتے ہیں اور رائے عامہ کے سامنے حکومت کا غرور کوئی معنی نہیں رکھتا۔ شاید یہ آزاد ہندوستان کی پہلی سرکار ہے جو یہ تاثر پیدا کرنے کی ناکام کوشش کرتی ہے کہ اس کا کیا ہوا ہر کام اور ہر فیصلہ حرف آخر ہوتا ہے۔ مگر جمہوریت بلاشبہ ایک ایسا نظام حکومت ہے جو عوام کے ووٹوں سے، عوام کے لیے، عوام کے ذریعہ چلایا جاتا ہے۔ ماضی میں بھی جن طاقتوں نے اقتدار کے کھمبے میں عوامی انگلوں کو درکنار کر کے من مانی کرنے کی کوشش کی ہے، وہ نشان عبرت

بنادی گئی ہیں۔ متنازعہ زرعی قوانین کے خلاف کسان گزشتہ ایک سال سے تحریک چلا رہے تھے۔ انھوں نے اس دوران بہت مصیبتوں کا مقابلہ کیا۔ شدید سردی اور بارش کے موسم میں بھی وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے۔ اپنے اتحاد اور عزم سے انھوں نے پورے ملک میں ان قوانین کے خلاف رائے عامہ کو بیدار کیا۔ لیکن حکومت اپنی ساری توانائی ان قوانین کی خوبیوں کو بیان کرنے میں لگاتی رہی۔ حکومت کا خیال تھا کہ کسان پوزیشن کے آگے کار ہیں اور دیر سویر ہتھیار ڈال دیں گے۔ بعد میں کسان تحریک کی کامیابی دیکھ کر حکومت متنازعہ قوانین میں ترمیم پر توجہ مرکوز ہو گئی، لیکن مکمل واپسی میں اسے اپنی توہین محسوس ہو رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ کسانوں کے اصل مطالبات پر کان دھرنے کی بجائے انھیں بدنام کرنے کی ممکن کوشش کی گئی۔ انھیں خالصتائی، موالی اور نہ جانے کیا کیا کہا گیا۔ حکمراں جماعت کے عام کارکن ہی نہیں ذمہ دار عہدوں پر بیٹھے ہوئے وزیر بھی ان کے خلاف بھڑاس نکالنے میں پیچھے نہیں تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ کسانوں نے ان کی دم پر اپنا پاؤں رکھ دیا ہے۔ حالانکہ کسانوں کی تحریک پوری طرح پرامن تھی اور وہ گاندھینی طریقوں سے احتجاج کے جمہوری حق کا استعمال کر رہے تھے، لیکن ایسا کوئی الزام نہیں تھا جو انھیں بدنام کرنے کے لیے نہ لگایا گیا ہو۔ ان کے حوصلوں کو توڑنے کے لیے تشدد کا بھی راستہ اختیار کیا گیا

ان میں پھوٹ ڈالنے کی بھی کوششیں ہوئیں اور انھیں راستوں سے ہٹانے کے لیے کچلا بھی گیا۔ اس سلسلہ کا سب سے دردناک واقعہ پچھلے دنوں اتر پردیش کے لکھیم پور کھیری میں پیش آیا، جہاں ایک مرکزی وزیر کے بیٹے نے دھرنے پر بیٹھے کسانوں پر اپنی گاڑی چڑھادی۔ اس سانحہ میں کئی کسانوں کی موت واقع ہو گئی۔ مجموعی طور پر اس تحریک کے دوران 650 سے زیادہ کسانوں نے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ المیہ یہ ہے کہ حکومت کے کسی کارندے نے ان کی موت پر ایک آنسو بھی نہیں بہایا۔ سبھی جانتے ہیں کہ اس حکومت کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ اقتدار کے گھنٹہ میں کسی کو خاطر میں نہیں لاتی۔ جو لوگ اس کے خلاف زبان کھولتے ہیں، ان کا گلا گھونٹنے کی کوشش ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ شہریت ترمیمی قانون اور این آر سی کے خلاف تحریک میں جن لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، وہ سبھی آج مسلمانوں کے پیچھے ہیں۔ انھیں شمال مشرقی دہلی کے فساد کا مسٹر مائنڈ قرار دے کر جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے۔ ان کے خلاف دہشت گردی مخالف قانون پوراے پی اے کے تحت مقدمات قائم کئے گئے تاکہ انھیں ضمانت ہی نہ مل سکے۔ اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ بی جے پی اپنے سیاسی اور نظریاتی مخالفین کے ساتھ وہی سلوک کر رہی ہے جو اندرا گاندھی نے بیکر جنسی کے دوران کیا تھا۔ (بقیہ صفحہ 12 پر)

مسلمانوں کو گرو دواروں میں کارسیوا انجام دینی چاہیے

ظفر آغا



گروگرام کی گرو دوارہ ایسوسی ایشن نے جمعہ کی نماز کے لیے گرو دواروں کی پیش کش کر جو احسان کیا ہے، مسلمان اس احسان کو چکانے کے لیے گرو دواروں میں لنگر کریں اور گرو دواروں میں کارسیوا انجام دیں

اس ملک پر بھلے ہی ہندوؤا سیاست کا کتنا ہی رنگ چڑھ گیا ہے۔ ہندوستان بھلے ہی ہندو راشنری ڈیلیز پر کیوں نہ کھڑا ہو۔ لیکن آج بھی عوامی سطح پر اس ملک کی لنگا۔ جنی روح زندہ ہے۔ اگر آپ کو یہ حقیقت دکھانی ہے تو آئیے آپ کو لے چلتے ہیں وہاں کے نزدیک (بلکہ اب وہ کم بیش وہاں کا ہی حصہ ہے) گروگرام، جو ابھی کچھ عرصے قبل تک گڑگاؤں کہلاتا تھا۔ لیکن اس سے قبل یہ یاد دہانی کروادیں کہ تقریباً دو ہفتے قبل گروگرام انتظامیہ نے وہاں آٹھ مقامات پر ہونے والی جمعہ کی نماز پر پابندی لگادی تھی۔ یہ آٹھ جگہ ہیں پارک وغیرہ جیسے مقام تھے جہاں ہندوؤا یعنی بی بی جے پی حامیوں نے نماز پڑھے جانے پر اعتراض کیا۔ پھر بچنگ دل کے لوگوں نے ایک جمعہ کے روز جہاں نماز ہو رہی تھی وہاں احتجاج کیا۔ انتظامیہ نے بچنگ دل اور نماز مخالفین کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے آٹھ مقامات پر جمعہ کی نماز پڑھے جانے پر پابندی لگادی۔ ظاہر ہے کہ یہ قدم بی بی جے پی کے اشارے پر انتظامیہ نے اٹھایا ہوگا۔ کیونکہ بی بی جے پی کو آئے دن مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری ثابت کرتے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔

الغرض، آٹھ مقامات پر گروگرام میں جمعہ کی نماز بند ہوگئی۔ گروگرام ایک انڈسٹریل مقام ہے جہاں لاکھوں کی تعداد میں مسلم آبادی بس چکی ہے۔ وہاں محض دو یا تین مساجد ہیں، جب کہ سنتے ہیں آزاد کی قبل کی کئی سومساجد بند پڑی ہیں۔ الغرض مساجد کی تنگی

ہے اور اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ جیسا عرض کیا کہ یہ سکھ قوم کا مسلمانوں پر احسان ہے، اب ہندوستانی مسلمانوں کا یہ فریضہ ہے کہ وہ سکھوں کے اس احسان کا جواب ایسے قدم اٹھا کر دیں جس سے سکھ مذہب کے تین احترام کا جذبہ ٹپکتا ہو۔ اور وہ محض دو ہی طریقے ہیں۔ اولاً سکھ گرو دواروں میں روز لنگر چلتے ہیں جس میں ہر شخص کو بلا تفریق مذہب ولت لنگر کا کھانا کھلایا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ محض گروگرام ہی نہیں بلکہ جہاں جہاں بھی ممکن ہو وہاں لنگر میں خرچ ہونے والی اناج و دیگر اشیاء ہدیہ کریں۔ اس کے علاوہ سکھ برادری گرو دواروں میں کارسیوا روز کرتے ہیں۔ مسلم نوجوان بچوں کو چاہیے کہ اتوار کے روز اپنے پڑوس کے گرو دواروں میں جا کر کم از کم دو گھنٹے کارسیوا انجام دیں اور یہ کام مولویوں کی قیادت کے بجائے پڑھے لکھے مسلم نوجوانوں کی قیادت میں ہونا چاہیے۔ گروگرام کی گرو دوارہ ایسوسی ایشن نے جمعہ کی نماز کے لیے گرو دواروں کی پیش کش کر جو احسان کیا ہے، مسلمان اس احسان کو چکانے کے لیے گرو دواروں میں لنگر کریں اور گرو دواروں میں کارسیوا انجام دیں۔ اس طرح مسلم۔ سکھ اتحاد مزید مستحکم ہوگی اور بی بی جے پی کی منافرت کی سیاست کمزور ہوگی۔

کے سبب وہاں کی مسلم بادی پارک جیسے عوامی مقامات پر نماز پڑھنے پر مجبور تھی۔ لیکن اب ایسی جگہوں پر بھی نماز پڑھنا محال ہوتا جا رہا ہے۔ بے چارہ گروگرام کا مسلمان دل موسس کر رہ گیا۔ اس مودی کے ہندوستان میں وہ کرتا بھی تو کرتا کیا۔ لیکن ابھی وہ مایوسی کے عالم میں جی رہا تھا کہ یکا یک عوامی سطح پر یہ خبریں آنی شروع ہوئیں کہ ہندو بھائیوں نے نماز کے لیے اپنے گھر مسلمانوں کو جمعہ کے لیے پیش کر دیے۔ ابھی یہ خبر آئی ہی تھی کہ تین روز قبل گروگرام گرو دوارہ ایسوسی ایشن نے گروگرام کے تمام گرو دواروں کے دروازے جمعہ کی نماز کے لیے کھول دیے۔ اس طرح اللہ کی طرف سے جمعہ کی نماز کا نشیبی انتظام ہو گیا اور انتظامیہ وہ بی بی جے پی کے حامیوں کے منہ لٹک گئے۔ کچھ ہندو بھائیوں اور سکھ گرو دوارہ ایسوسی ایشن نے مسلمانوں کی نماز کے لیے جو کام کیا ہے، وہ محض قابل ستائش ہی نہیں بلکہ قابل صدا احترام ہے۔ جمعہ جیسی اہم نماز کے لیے سکھ بھائیوں نے گرو دواروں کو کھول کر جو کام کیا ہے، وہ مسلم قوم پر کسی احسان سے کم نہیں ہے۔ کیونکہ یہ محض مقامی انتظامیہ کے منہ پر ایک چائنا ہی نہیں بلکہ بی بی جے پی کی مسلم منافرت کی سیاست کا ایک کارا جواب بھی ہے۔ مودی کے دور میں سکھوں کی یہ جرات قابل صدا احترام

شیر میسور ٹیپو سلطان کی رواداری

شاہد صدیقی علیگ

مؤرخ تیری رنگ آمیزیاں تو خوب ہیں لیکن کہیں تاریخ ہو جائے نہ افسانوں سے وابستہ سلطان فتح علی خاں ٹیپو ایک عادل حکمران، ایک اعلیٰ منتظم، ایک مستقبل شناس، ایک مرد مجاہد اور ایک عظیم سپہ سالار ہی نہیں بلکہ ایک مدبر، ایک قادر الکلام شاعر اور ایک اسکالر بھی تھا جسے آزادی کا جذبہ، جرأت، شجاعت، عزم و استقلال، سخت کوشی، خطر پسندی اور جنگی حکمت عملی ورثے میں ملی تھی۔ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ ہندوستان کے طول و عرض پر اگر کسی نے انگریزوں کے دانت کھٹے کیے تو وہ سلطان حیدر علی اور ان کے فرزند ارجمند ٹیپو سلطان ہی تھے۔ جن کی ذہانت، فراست، مستقبل شناسی اور قائدانہ طلسمی صلاحیت کے آگے انگریز بے بس نظر آئے۔ جب تک ٹیپو سلطان کی آخری سانس باقی رہی فریبی فریبگیوں کا حال آشفتمند اور مستقبل لاپتہ رہا، چنانچہ انہوں کی غدار یوں، مراٹھوں اور نظام کے ناپاک گٹھ جوڑی بدولت جب 4 مئی 1799 کو ٹیپو سلطان کی رگوں کا سارا ہڈی میسور کی خاک میں جذب ہو گیا، تو اس کی خبر انگریز جنرل ہارس کو جیسے ہی ملی تو فرط خوشی سے جھوم اٹھا کہ ”آج ہندوستان ہمارا ہے۔“ فرنگیوں نے وسیع نظر، انصاف پسند اور راجا پور و شیر میسور کے بارے میں من گھڑت اور بے بنیاد افسانے گھڑ کر گمراہ کن مواد پیش کیا، تاکہ ہندوستان کی قدیم ہم آہنگی، رواداری اور آپسی رشتوں کو تار تار کیا جاسکے۔ ان کے جھوٹے حقائق اور زہر آلودہ باتیں ڈبلو کرک پیٹرک کی سلیکٹ لیزرز آف ٹیپو سلطان (1811)، ایم وکس کی ہسٹوریکل اسکچس آف ساؤتھ انڈیا (1864) اور ایچ۔ ایچ۔ ڈوڈویل کی کیمبرج ہسٹری آف انڈیا (1929) جیسی تصانیف کے اوراق میں بکھری ہوئیں دیکھی جاسکتی ہیں، جبکہ سلطنت خداداد کے حقیقی و تاریخی دستاویزات فارسی اور اردو زبانوں میں ہیں، جن پر آج بھی لاپرواہی

اور بے حسی کی دبیز چادر پڑی ہوئی ہے۔

ٹیپو سلطان کے بارے میں گیان پیٹھ ایوارڈ یافتہ گریش کرناڈ کا بیان قابل ستائش ہے کہ، ”ٹیپو سلطان مسلمان ہونے کے بجائے ہندو ہوتے تو انہیں بھی شیوا جی جیسا اعزاز ملتا گویا شیر میسور کے ساتھ صرف مذہب کی بنیاد پر سوتیلا برتاؤ روا رکھا گیا۔“ فتح علی ٹیپو سلطان



ایک کشادہ ذہن کے فرمانروا تھے۔ وہ جتنے بہادر تھے، اتنے ہی خداترس اور عصبیت سے پاک بھی تھے۔ ان کی نظروں میں ہندو اور مسلمان دونوں ہی برابر تھے۔ ٹیپو سلطان کی رواداری کی اس سے بڑی مثال کیا ہوگی کہ ٹیپو سلطان کا میر آصف (مالیات اور مال گزارا) پنڈت پورنا، خزانچی کرشنا راؤ، شامیا یا آئینگر وزیر) ڈاک و پولیس)، اس کا بھائی رنگا آئینگر بھی ایک افسر تھا، مول چند وسجن رائے مغل دربار میں اس کے چیف ایجنٹ تھے اور ان کا خاص پیش کار ساراؤ بھی ایک ہندو تھا۔ سری نواس راؤ اور پاجی رام ان کے قریبی ساتھی تھے۔ کورک کا فوجدار ناگپاہا ایک برہمن تھا۔ کونجور اور بالگھٹا کے ریونیو آفیسر برہمن تھے۔ ٹیپو کی بے قاعدہ گھوڑ سواری فوج کا سربراہ ہری سنگھ تھا۔ راماراؤ اور سیواجی کے ہاتھوں میں باقاعدہ گھوڑ سواری سستے کی کمان تھی۔ ٹیپو نے جنرل سری پت راؤ کو مالابار میں نازوں کی بغاوت کو دبانے کے لیے روانہ کیا تھا۔ ان کی فوج میں فرانسسی

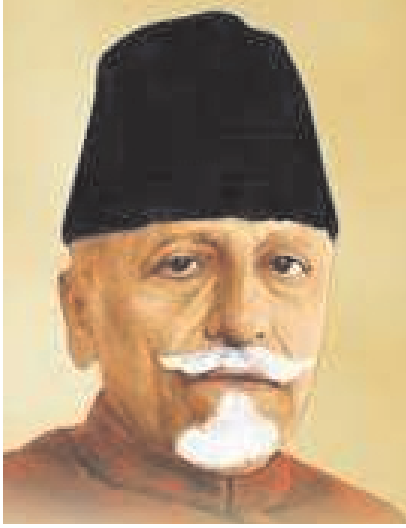
عیسائی بھی اعلیٰ منصبوں پر مامور تھے۔ میسور کی تاریخ میں پہلا چرچ فرانسسیوں کی گزارش پر ان کی اجازت سے تعمیر ہوا۔

ٹیپو سلطان ایک انتہائی سیکولر اور منصف مزاج شخصیت کا مالک تھا جس نے بلا تفریق مذہب و ملت اپنی رعایا کیلئے کام کیا۔ میسور گزٹ کے مدیر پروفیسر سری کانتایا نے 156 مندروں اور مٹھوں کی فہرست دی ہے جن کو ٹیپو باقاعدگی سے سالانہ عطیہ دیتے تھے۔ ٹیپو سلطان اور مندروں کے مابین خط و کتابت، کئی مندروں کو زیورات اور اراضی عطیہ کرنے کے فرمان آج بھی موجود ہیں۔ 1782 اور 1799 کے درمیان ٹیپو سلطان نے اپنی سلطنت میں مندروں کو وقف کے 34 سنجاری کیے، جبکہ بہت سے مندار کو سونے اور چاندی کی پلیٹوں کے تحفے بھی پیش کیے۔ جب سرنگری کے مٹھ کو مراٹھوں نے تاخت و تاراج کر دیا تھا تب ٹیپو ہی نے اس مٹھ کو از سر نو تعمیر کروایا تھا۔ ٹیپو سلطان نے مراٹھوں کی بددیانتی عمل پر افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا کہ۔ ”جو لوگ ایسے گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں جس میں عبادتگاہوں کے نقصان پہنچایا جائے تو انہیں اس کی سزا کل یک میں ہی جانی ہے۔“ فار آف نیشن مہاتما گاندھی بنگ انڈیا کے 23 جنوری 1930ء کے شمارے میں ٹیپو سلطان کی رواداری کو یوں سراہتے ہیں کہ: غیر ملکی مضمین میسور کے فتح علی ٹیپو سلطان کو ایک سخت گیر جنونی کے طور پر پیش کر کرتے ہیں، جس نے اپنی ہندو رعایا پر ظلم ڈھائے اور انہیں زبردستی اسلام مذہب قبول کرنے پر مجبور کیا، جبکہ اس کے ہندو رعایا کے ساتھ تعلقات بالکل خوشگوار نوعیت کے تھے۔ میسور ریاست کے محکمہ آثار قدیمہ کے پاس تیس سے زیادہ خطوط موجود ہیں جو ٹیپو نے شرنگیری کے شکر آچاریہ کو لکھے تھے جو کنڈ زبان میں ہیں۔ یقینی طور پر ٹیپو کل مختار بادشاہ تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے ہندو تاجروں کو عربی رسم الخط میں اپنا حساب کتاب رکھنے پر مجبور نہ کیا۔

(بقیہ صفحہ 12 پر)

مولانا آزاد ایک عظیم مجاہد آزادی

شاہد صدیقی علیگ



1905ء نے ان کے اوپر گہرے اثرات مرتب کیے، اسی اثنا میں 1905ء میں ان کا تعارف شیام سندر چکرورتی سے ہوا جو کانگریسی رضا کاروں میں ایک بڑا ترسہ رکھتے تھے، جنہوں نے دوسرے حریت پسندوں سے بھی مولانا کو متعارف کرایا، تو انہیں بہت حیرت ہوئی، شروع میں انہیں ان کے اوپر بھروسہ نہیں تھا اور انہوں نے اپنی خفیہ میٹنگوں سے دور رکھنے کی کوشش کی، تاہم رفتہ رفتہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ ان کے قابل اعتماد ساتھی بن گئے۔ 1908ء میں انہوں نے مصر، عراق، شام اور ترکی کا سفر کیا، جو جب وہاں کے سیاسی و سماجی حالات کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملا۔ بیرونی ممالک کے رہنماؤں سے گفتگو کرنے کے بعد مولانا آزاد تحریک آزادی میں سرگرم حصہ ادا کرنے کے لیے ذہنی طور پر بھی تیار ہو گئے، انہوں نے اپنے خیالات عوام تک پہنچانے کے لیے 12 جون 1912ء کو الہمال کا پہلا شمارہ شائع کیا جس نے قیل مدت میں ملکی سیاست میں ہنگامہ برپا کر دیا تھا نیز مسلمانوں کے سیاسی شعور میں بھی عظیم انقلاب پیدا کر دیا۔ حکومت نے خوفزدہ ہو کر 18 ستمبر 1913ء کو پریس ایکٹ کے تحت دو ویزارو پے کی ضمانت طلب کی، جسے ادا کر دی گئی مگر اس کے بعد حکومت نے 10000 رپڑار کی ضمانت طلب کی اسے بھی ادا کر دی گئی، لیکن حکام کی منشا کچھ اور تھی لہذا 18 نومبر 1914ء کو الہمال ضبط کر لیا، مگر جلد ہی انہوں نے نومبر 1915ء میں البلاغ نام سے دوسرا پرچہ شروع کر دیا، مولانا آزادی کی اس جرأت پر بنگال گورنمنٹ آپ سے باہر ہو گئی، اس نے ڈیفینس آف انڈیا ریگولیشنز کی دفعہ کے تحت انہیں شہر بدر کا حکم سنا دیا، ساتھ ہی سمبلی، پنجاب، دہلی اور متحدہ صوبوں میں ان کے داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی، چنانچہ 23 مارچ 1916ء کو مولانا آزاد کلکتہ سے رانچی چلے آئے۔ جہاں ان کے کامیوں نے 60 رپڑار افراد کے دستخطوں کا ایک میورنڈم حکومت کو پیش کیا، تاکہ مولانا آزادی کی نظر بندی اور جلا وطنی جلد ختم کر دی جائے، مگر حکومت کے کانوں پر جوں نہیں رہتی۔ اس نے ان کے لئے 8 جولائی 1916ء کو ان کی نظر بندی کا حکم دے دیا، غالباً چار سال قید فرنگ کے بعد رہائی عمل میں آئی۔ مہاتما گاندھی

مولانا ابوالکلام ہندوستان کی تاریخ ساز شخصیتوں میں منفرد حیثیت کے حامل ہیں، جو 11 نومبر 1888ء مطابق 1305ھ کو مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام محمد خیر الدین اور والدہ کا نام عالیہ بنت محمد تھا، ان کا خاندان ان کی پیدائش کے دو سال بعد کلکتہ منتقل ہو گیا۔ انہوں نے ادب، دین، صحافت یا سیاست جس میدان میں بھی قدم رکھا، اس میں اپنے عظیم نقوش مرتب کیے، انہوں نے جس دور میں شعور کی آنکھیں کھولیں وہ ملک عزیز پر برطانوی حکومت کے ظلم و ستم کا دور شباب تھا، ایک طرف نئے نئے قانون کی آڑ میں ہندوستانیوں کا عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا تھا تو دوسری جانب انگریزی ایوانوں میں انہوں نے وطن کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرنے کی حکمت عملیاں وضع کی جا رہی تھیں۔ مولانا آزاد غیر معمولی صلاحیتوں کے پیکر تھے۔ محض 11 سال کی عمر میں ہی داغ دہلوی اور امیر مینائی کے پاس اصلاح کے لیے اپنے کلام بھیجنے لگے تو 12 برس میں ایک رسالہ ”نیرنگ عالم“ شروع کیا۔ تیرہ سال کی عمر میں ادبی تحقید پر مضامین لکھے۔ آپ کی یادداشت کے کیا کہنے کہ ایک نظر ڈالی اور ابرہ ہو گیا۔ مولانا کو 1903ء میں پندرہ سال کی عمر میں پہلی مرتبہ تقریر کا موقع ملا، دوسری مرتبہ اگلے سال انجمن اسلام کے لاہور کے جلسہ کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے ایسی فصیح و بلیغ صدارتی تقریر کی کہ حاضرین ان کے گرد بیٹھ بن گئے، جس کی بنا پر ان کو ابوالکلام کے خطاب سے نوازا گیا۔ مولانا آزاد کو بچپن سے ہی خطاب کرنے کا شوق تھا، جس کے بارے میں مولانا کی ہمیشہ خدیجہ بیگم کہتی ہے کہ: ”آزاد کو بچپن ہی سے خطیب بننے کا شوق تھا، چنانچہ کبھی کبھی وہ گھر میں کسی اونچی جگہ کھڑے ہو جاتے اور سب بہنوں کو اس پاس کھڑا کر کے کہتے کہ تم لوگ تالیان، بجاؤ اور سمجھو کہ ہزاروں آدمی چاروں طرف کھڑے ہیں اور میں تقریر کر رہا ہوں اور لوگ میری تقریر سن کر تالیان، بجا رہے ہیں۔“ صرف 16 سال کی عمر میں مولانا آزاد کے سیاسی تفکرات نمودار ہونے شروع ہو گئے تھے، تقسیم بنگال

نے 1920ء میں جب عدم تعاون تحریک کی تجویز پیش کی تو مولانا آزاد نے غیر مشروط طور پر اس کو قبول کر لیا، جبکہ کچھ قائدین ابھی شش و پنج میں تھے، عدم تعاون تحریک کے پیش نظر ناگپور کا جلسہ دسمبر 1920ء میں ہوا، جس کی پاداش میں دسمبر 1921ء میں ہی آرداس کے ساتھ پرینڈی جیل میں پور میں قید کر دیا گیا۔ جب مولانا آزاد رہا ہو کر باہر نکلے تو کانگریس آہستہ آہستہ ہندی میں منقسم ہوتی نظر آ رہی تھی، تو انہوں نے اتحاد کو وقت کی اہم ضرورت سمجھتے ہوئے رہنماؤں کے مابین مفاہمت کی تاک دو شروع کی جس میں 1923ء کے خصوصی اجلاس میں کامیابی ملی، ان کی اعلیٰ قائدانہ صلاحیتوں کو پیشتر لیڈران محسوس کر چکے تھے۔ چنانچہ انہیں کانگریس کا قومی صدر منتخب کر لیا گیا جو کانگریس کی تاریخ میں سب سے جوان سال (35) صدر تھے۔ 12 مارچ 1930ء کو ڈانڈی مارچ میں گاندھی جی سمیت ملک کے قدامت مسلمان رہنماؤں نے بھی حصہ لیا، نمک قانون کی تحریک میں کامیابی ملنے کے بعد حکومت کی تیز سختی ہو گئے، اس کے نتیجے میں حکومت نے ان رہنماؤں کو جیلوں میں بھر دیا تھا۔ مولانا کو گرفتار کر کے میرٹھ جیل میں ڈال دیا گیا، جہاں سے وہ ڈیڑھ سال بعد چھوٹے۔ 1935ء کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کا نفاذ عمل میں آنے کے بعد کانگریس نے پہلی بار مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کے ایکشن میں حصہ لینا قبول کیا، جبکہ صوبوں کی خود مختاری کے معاملے میں کانگریس کا ایک ڈھڑا ایکشن کی مخالفت کر رہا تھا مگر مولانا آزاد کے نزدیک کانگریس کو اپنی مقبولیت کا ثبوت فراہم کرنے کے لیے اس سے اچھا موقع نہیں مل سکتا۔

زرعی قوانین کی واپسی سے حزب اختلاف کا مدعہ ختم نہیں ہوگا

پروفیسر عتیق احمد فاروقی

دینک جاگرن میں سیاسی تجزیہ کار اور سینئر کالم نگار پردیپ سنگھ کا ایک مضمون میری نظروں سے گزر جس میں انہوں نے خیال ظاہر کیا ہے کہ زرعی قوانین کی واپسی سے حزب اختلاف کا مدعہ ختم ہو گیا ہے اور اس سے بی-بی کو انتخابات میں پورا فائدہ حاصل ہوگا۔ وہ اور

دوسرے تمام مودی نواز بیبی کہتے رہے ہیں کہ زرعی قوانین کسانوں کے مفاد میں ہے، کسان اس حقیقت کو سمجھ نہیں پارے ہیں۔ مرکزی حکومت بھی ہمیشہ کسانوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتی رہی ہے کہ ان قوانین سے کسانوں کی آمدنی دوگنی ہو جائے گی۔ وہ پورے ملک میں اپنی پیداوار کہیں بھی فروخت کرنے کیلئے آزاد ہوں

گے۔ مٹی کی نظام پہلے ہی کی طرح قائم رہے گا اور ایم ایس پی قانون کا نفاذ پہلے ہی کی طرح ہوگا۔ کسان لیڈران اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ تمام مبینہ فوائد ملنے کے امکانات کے باوجود وہ احتجاج و مظاہرہ کریں اور اپنی ضد میں قریب 700 کسانوں کی جائیں قربان کر دیں۔ احتجاج کرنے سے پہلے انہوں نے بھی دانشوروں اور زرعی ماہرین سے مشورہ کیا ہوگا اور مسئلے کے تمام پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد ہی احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا ہوگا۔ حکومت کی بنیادی غلطی یہ ہے کہ ان قوانین کا مسودہ تیار کرنے سے پہلے کسان لیڈران اور زرعی ماہرین سے مشورہ کرنا چاہیے تھا۔ دوسرے، جس عجلت سے متعلقہ بل پارلیمنٹ میں پاس کرایا گیا وہ بھی شکوک پیدا کرنے کا ایک بڑا سبب ہے۔ کم از کم حکومت کو حزب اختلاف کا بل کو سلیٹ کمیٹی میں بھیجنے کا مطالبہ مان لینا چاہیے تھا۔

حکومت کی یہ دلیل ہے کہ کسان اپنی پیداوار پورے ملک میں ملک میں فروخت کرنے کا مجاز ہوگا قابل فہم نہیں ہے۔ چھوٹے اور متوسط طبقہ کے کسانوں کے پاس نہ اتنے وسائل ہیں اور نہ وقت ہے کہ وہ اپنی پیداوار پورے ملک میں بھیجیں۔ عملی طور پر یہ بات ناقابل قبول ہے۔ اس نظام سے جو بڑے صنعتی گھرانے ہیں ان کو

یقیناً فائدہ پہنچے گا جن کے بارے میں یہ اطلاع ہے کہ ان لوگوں نے بڑے بڑے گودام بنوائے ہیں۔ وہ ہورڈنگ کر کے کسانوں کی پیداوار کا فائدہ اٹھائیں گے۔ پچارے کسانوں کو اپنی پیداوار فروخت کرنے کیلئے ان کی شرطوں کو ماننا



پڑے گا۔ وہ کسان اپنی شکایتوں کو لیکر عدالت کا دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹا سکتے۔ ان کے تنازعہ کو نمٹانے کا اختیار مقامی افسران کو دیا گیا ہے۔ ان قوانین کے تعلق سے کسانوں کے دوسرے مطالبات بھی ہیں۔ ان میں سے ایک مطالبہ یقیناً ایسا تھا جس کو اگر مرکزی حکومت مان لیتی تو کسان دوسرے مطالبات کی یقین دہانی پر ہی اپنے احتجاج کو ختم کرنے کے بارے میں غور کرتا۔ وہ مطالبہ تھا ایم۔ ایس۔ پی کو قانونی شکل دینا۔ جیسا کہ راکیش گلپت نے اپنے ردعمل میں کہا کہ مرکزی حکومت کا فیصلہ زرعی ہے۔ زرعی قوانین کے خلاف جاری کسانوں کی تحریک ابھی ختم نہیں ہوگی اور مستقبل کا لائحہ عمل چند دنوں میں طے ہوگا۔ انہوں نے واضح کیا کہ جب تک حکومت اس سے متعلق دوسرے مطالبات نہیں مان لیتی احتجاج ختم ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ دیگر مطالبات میں کسانوں پر درج جھوٹے مقدمات کی واپسی، پارلیمانی اجلاس میں زرعی قوانین کی واپسی کی منظوری، مظاہرے اور دھرنے کے دوران شہید ہونے والے کسانوں کو معقول معاوضہ، بجلی کا بل 2020 کی واپسی، ایئر کواٹی سے متعلق قانون متحدہ کسان مورچہ اور زرعی ماہرین کے

مشورہ سے مرتب کیا جانا اور لکھنؤ پور کھیری تشدد معاملے میں مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ کو برخاست کیا جانا شامل ہے۔

حیرت کی بات یہ ہے کہ پردیپ سنگھ جی فرماتے ہیں کہ وزیر اعظم کے اس اعلان سے پورے حزب اختلاف کی ہوا نکل گئی ہے کیونکہ جس مدعہ کو لیے وہ گھوم رہے تھے وہ مدعہ ہی ختم ہو گیا۔ وہ اس بات کو بالکل نہیں سمجھ رہے ہیں کہ قوانین کے واپسی کے اعلان سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ ابھی مسئلہ اسی شکل میں زندہ ہے۔ جب تک حکومت مبینہ مطالبات مان نہیں لیتی تب تک کسانوں کا احتجاج ختم ہونے والا نہیں ہے۔ پردیپ سنگھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ

ملک بھر کے زرعی ماہرین اور اقتصادیات کے ماہرین ان قوانین کو فائدے مند بتا رہے ہیں۔ دراصل غیر جانب دار ماہرین ان قوانین کے نقصانات کی نشاندہی کر رہے ہیں اور وہ ماہرین جو سرکاری عہدے پر فائز ہیں وہ ان قوانین کے فوائد کی باتیں کر رہے ہیں جو کہ ان کی مجبوری ہے۔ پردیپ جی کا یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ یہ احتجاج ڈھائی ریاستوں (پنجاب، ہریانہ اور مغربی یوپی) تک محدود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ملک گیر احتجاج ہے جس کی گونج مغربی بنگال اور جنوبی ہندوستان کے انتخابات میں ہم لوگ سن چکے ہیں۔ موصوف نے فرمایا کہ یہ مدعہ حزب مخالف کیلئے سیاسی اے۔ ٹی۔ ایم تھا جسے مودی جی نے بند کر دیا ہے۔ یہ بھی ان کی خوش فہمی ہے کیونکہ یہ اے۔ ٹی۔ ایم اب اور سرگرم ہو گیا ہے۔ دراصل آئندہ ہونے والے ریاستی انتخابات کے مد نظر وزیر اعظم کو مجبوراً زرعی قوانین کی واپسی کا فیصلہ کرنا پڑا ہے۔ انتخابات میں اس سے بی-بی کو کتنا فائدہ ہوگا یہ اس بات پر منحصر ہے کہ وہ کہاں تک مبینہ اقدام کرتی ہیں اور عوام کا اعتماد وزیر اعظم کو کہاں تک حاصل ہے؟ اگر ان کی نیت صاف ہے تو انہیں کسانوں کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے۔

☆☆☆

تبادلہ خیال مؤثر درس و تدریس کے عمل کے لیے ضروری ہے۔ یہ ایک اہم تدریسی سرگرمی ہے جس کے بغیر خیالات، مشاہدات، تجربات کا تبادلہ ممکن نہیں۔ یہ تدریسی عمل کا ذریعہ ہے نہ کہ مقصد جو کسی بھی تدریسی سرگرمی کے مقاصد یا ناکسس کو مؤثر انداز میں حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ معلم بغیر کسی واسطے کے اس عمل میں شامل ہیں جن کا طلباء کے ساتھ رابطہ معمول کا ہے، جو تسلسل کے ساتھ زبانی اور تحریری دونوں انداز میں خیالات، آراء یا معلومات دیتے اور وصول کرتے ہیں۔ اس تبادلہ خیال میں زبان کا استعمال بہت اہم ہے۔ افراد اپنے اپنے فریم میں زبان کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اس لیے مختلف لوگوں سے کہے گئے ایک جیسے الفاظ مختلف رد عمل پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح تبادلہ خیال کے لیے وقت کا موزوں ہونا بھی اہم ہے۔ کبھی تبادلہ خیال کی ضرورت ہوتی ہے، اور کسی وقت میں اس کی

ضرورت نہیں ہوتی اور کبھی معلومات، تجربات کے تبادلے میں تاخیر و اشد مندی کا عمل ہوتا ہے۔ خاص طور پر وہاں جب تنازع کی صورت حال سے باہر آنا ہو۔ تبادلہ خیال صرف اظہار نہیں، بل کہ ایک تاثر بھی ہے۔ معلومات اور تجربات کس قدر مؤثر ہیں اس کا اندازہ اسی صورت میں ممکن ہے جب طلباء یا سامعین سے اس بارے فیڈ بیک لیا جائے۔ تبادلہ خیال میں معلم کی زبان کا قابل فہم ہونا ضروری ہے۔ ایسی زبان استعمال کرنا جسے طلباء نہیں سمجھ سکتے، اس کا کوئی مثبت نتیجہ نہیں دیتا۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ استاد کلاس کو مصروف رکھنے کے لیے ایسے بول بولے: "اس لیے ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے، آپ کا یہ دائرہ ہے، آپ اس سے باہر نہیں آئیں گے، وگرنہ میں آپ کو سزا دوں گا۔" طلباء اس وقت ہی نئے خیالات کو سمجھ سکیں گے اگر معلم چیزوں میں موازنہ کرنا سکھائے یا مثالیں دے، یا اس سے ملتے جلتے حوالے دے۔ جتنا ممکن ہو اپنی بات کو اختصار دے۔ گفتگو کرتے ہوئے اہم الفاظ اور فقرات پر زور دے، یا ان کو ڈہرائے۔ اگر وہ طلباء کی سیکھنے، تکرار اور صراحت میں مدد دے تو یہ قابل تفسیر عمل ہے۔ لیکن معلم کے بات کرنے سے ہی کمرہ جماعت میں خاموشی ہو جائے

تو عام طور پر ایسا تعلم غیر مؤثر ہے۔ معلم کا تبادلہ خیال صرف مضمون کی تدریس تک ہی نہیں بل کہ یہ معلم کا طلباء کے ساتھ انفرادی تعلق بھی پروان چڑھاتا ہے جو انہیں تعلم کی طرف رغبت دلانے کا باعث بنتا ہے۔ عام طور پر معلم کلاس ڈپلن کے لیے ٹیکیلو لینگویج استعمال کرتے ہیں جو ایک مثبت اپروچ نہیں ہے۔ یہ بات اہم ہے اگر شاگرد میں نظم پیدا کرنا ہو تو استاد کو مختلف زاویوں سے بات کرنی چاہیے تا کہ طلب علم سننے کی طرف مائل ہو۔ معلم کی آواز کلاس روم تبادلہ خیال میں ایک اہم عنصر ہے جو کسی موسیقی کے آلے جیسی ہے اگر اس کا بہتر استعمال کیا جائے، اسی صورت میں ہی طلباء قادر کرنے والے اور رد عمل ظاہر کریں گے۔ کچھ کی آواز بہت سے لوگوں کی نسبت فطری طور پر سننے میں

کلاس روم تبادلہ خیال اور استاد

آسان ہوتی ہے۔ آواز کی ایسی خاصیت معلم کا کردار مثالی بناتی ہے۔ کسی معلم کو تبادلہ خیال میں آواز کے اتار چڑھاؤ، اس کی بلندی، رفتار، دھیمے پن، شفافیت اور اس کے اظہار پر دھیان دینا چاہیے۔ سوال اچھے تبادلہ خیال کی بنیاد ہے سوالات معلم اور متعلم کے باہمی تعاون، تعلق سے ہی ممکن ہیں جو اچھی تدریس کی نشانی ہے۔ ایک مؤثر معلم درست یا حقیقی قسم کے سوالات پوچھتا ہے جو ان کے مقاصد کے ساتھ میل کھاتے ہوں۔ سوالات کی ترتیب، ان پر توجہ اور اس بارے مشکلات کے حل بارے مؤثر ہدایت ضروری ہیں۔ معلم کیے گئے سوالات بارے طلباء کو وقت دے تاکہ وہ تھرہ کر سکیں اور باقی طلباء اس بارے اپنا ریسپانس دے سکیں۔ اس بارے معلم کو تنگ دل نہیں ہونا چاہیے، بل کہ دوران تدریس طلباء کے ریسپانس کو محفوظ کرے۔ کیے گئے سوالات کا مقصد کیوں کہ طلباء کی توجہ معلم بارے مبذول کرانا ہوتی ہے یا ان کی توجہ کو چیک کرنا ہوتا ہے تاکہ ان کی تہذیب سمجھی جاسکی۔ معلم اگر کمرہ جماعت میں تنقیدی، تخلیقی ترقی کو نشوونما دینا چاہتا ہے تو اسے سوالات کے فن بارے جان کاری کرنی چاہیے۔ سوالات طلباء بارے جان کاری کا بہترین ذریعہ ہیں۔ کلاس روم دسکشن

ایک معلم کے لیے تبادلہ خیال کا اہم طریقہ ہے جس سے وہ طلباء کے لئے تعلم کو مؤثر بنا سکتا ہے۔ یہ اپروچ طلباء کو وہ مواقع دیتی ہے کہ وہ اپنی اقدار کو واضح کر سکیں، انکوائری کے عمل کو بڑھاوا دے سکیں اور پرامن سلوگ مہارتوں کو ترقی دے سکیں۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو معلم، متعلم کا تبادلہ خیال زیادہ تر شخصی ہے، جس میں ظاہری صورت، جسمانی حرکات، نشست و برخاست، چہرے کے تاثرات اور طرز گفتگو شامل ہیں۔ چہرے کے تاثرات تحریک، بدلاؤ اور منفی نتائج کا باعث ہو سکتے ہیں۔ دکھائی دینے والے چہرے کے تاثرات عام طور پر ادا ہوتے ہیں جن میں اہم مسکراہٹ ہے جس سے مسرت ملتی ہے۔ معلم کو چاہیے کہ وہ بچوں کے جذباتی حالات میں جس میں خوف، غصہ، غیظ و غضب، خوشی اور سر پر اڑنا شامل ہے۔ ایسے حالات میں معلم کو مسرت کے ملے جلے تاثرات سے طلباء تک تعلم پہنچانا چاہیے۔ ہماری آنکھیں نفرت، خوف اور احساس شرمندگی کو بہ راہ راست مشاہدہ کرتی ہیں، اسی طرح محبت و شفقت کو معلم تعلم دینے کے بعد کلاس

میں گھوم پھر تعلم کی کامیابی کا جائزہ لیتا ہے۔ اس کام میں وہ آنکھوں سے طلباء کے ساتھ ربط میں ہوتا ہے، جس میں وہ مشاہدہ کرتا ہے کہ کس طالب علم نے جواب دینا ہے یا کام مکمل کیا ہے یا کون سا ایزی بیٹھا ہے۔ اب معلم کو اس بارے لکیر کا فقیر یا ایک ہی الاٹھی سے سب کو نہیں ہانکنا چاہیے، بل کہ طلباء کے انفرادی مسائل کو گہرائی سے سمجھنا چاہیے۔ اس لئے معلم کا ایسا محتاط انداز طلباء کے بدلاؤ میں اہم ہے۔ اسی طرح غیر متوجہ یا غیر شائستہ حرکات والے طلباء سے خاموشی میں غلٹی لگی آنکھیں بالکل ایک مفید ذریعہ ہو سکتا ہے۔ جسمانی حرکات جس میں سر باز، ہاتھ اور جسم کے دوسرے حصے شامل ہیں مؤثر معلوماتی تبادلے کے ذرائع ہیں۔ معلم جب وائٹ بورڈ پر لکھنے کی طرف پوائنٹر کرتا ہے، اسی طرح طلباء اس وقت بھی متوجہ ہوتے ہیں جب استاد ڈیسک پر اپنا ہاتھ مارتا ہے یا اپنا پاؤں زمین پر مارتا ہے۔ ان میں سے ہر جسمانی عمل خاص معلومات کے تبادلے کا کام کرتا ہے۔ تاہم معلم کو جسمانی اشارات کے استعمال میں تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ حد سے زیادہ اشارات سے سنے جانے والے پیغام میں کیا اہم ہے اس کو ذہن نشین کرنے کا امکان کم ہی ہوگا۔

زرعی قوانین کی واپسی کا سبق

یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ کسانوں کی تحریک کے دو بڑے مراکز تھے۔ ان میں پہلا مرکز پنجاب تھا اور دوسرا یوپی۔ ان دونوں ہی صوبوں میں آئندہ چند مہینوں میں اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں۔ پنجاب میں اس وقت کانگریس کی سرکار ہے، جبکہ اتر پردیش میں خود بی جے پی اقتدار میں ہے۔ بی جے پی چاہتی ہے کہ وہ ایک طرف پنجاب کو کانگریس کے ہاتھوں سے چھینے تو وہیں یوپی میں دوبارہ اقتدار میں واپس آجائے۔ کسان تحریک کے انتخابی سیاست پر اثر انداز ہونے کا احساس بی جے پی کو حالیہ ضمنی الیکشن میں بہت شدت کے ساتھ ہوا۔ اپنے اقتدار والے صوبے ہماچل پردیش میں وہ اسمبلی کی تین اور پارلیمنٹ کی ایک سیٹ کانگریس سے ہار گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ہماچل میں سیب کی کاشت کرنے والے کسانوں نے بی جے پی کو ہارنے میں اہم کردار ادا کیا۔ یوں تو آئندہ چند مہینوں میں پانچ صوبائی اسمبلیوں میں چناؤ ہونے والے ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ اہمیت اتر پردیش اور پنجاب ہی کی ہے۔ مغربی یوپی کے کسانوں میں بی جے پی کے خلاف جو ماحول ہے، اس نے یوگی سرکار کے ہاتھ پاؤں پھلادے تھے۔ کسان لیڈر راکیش ملکیت نے حکومت کے ہر ظلم اور ان انصافی کا مقابلہ ہمت اور حوصلے کے ساتھ کیا۔ انھوں نے کسانوں کو واپس گھروں کو جانے کی ذریعہ اعظم کی اپیل کو ٹھکراتے ہوئے کہا ہے کہ کسان اس وقت تک اپنی جگہوں سے نہیں ہٹیں گے، جب تک پارلیمنٹ سے باقاعدہ ان قوانین کو رد کرنے کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ انھوں نے اس موقع پر کہا کہ سرکار ایم ایس بی کے ساتھ ساتھ کسانوں کے دیگر مطالبات پر بھی بات چیت کرے۔ اس طرح یہ واضح ہو گیا کہ کسان ابھی اپنا دھرنا جاری رکھیں گے اور وہ اس وقت تک اپنی جگہوں سے نہیں ہٹیں گے جب تک اس ماہ کے آخر میں پارلیمنٹ کا اجلاس شروع ہو جانے کے بعد ان قوانین پر واپسی کی مہر نہیں لگ جاتی۔

زرعی قوانین کی واپسی کا اعلان ہونے کے بعد شہریت ترمیمی قانون کو بھی واپس لینے کے مطالبات میں شدت پیدا ہو گئی ہے۔ سبھی جانتے ہیں کہ شہریت ترمیمی قانون کے خلاف جو ملک گیر احتجاج ہوا تھا اس کا مرکز دہلی کا شاہین باغ تھا۔ شاہین باغ میں لاکھوں انسانوں کا جھوم اٹھا یا تھا اور یہ جگہ قاہرہ کے تحریک برائے اسکواٹر کی طرح دنیا بھر میں مشہور ہو گئی تھی۔ اس دوران ملک میں کورونا کی وبا نے زور پکڑ لیا اور سپریم کورٹ کے سہارے اس تحریک کو ختم کر دیا گیا۔ لیکن شہریت ترمیمی قانون میں مسلمانوں کو الگ تھلگ کرنے کی جو کوشش کی گئی ہے، اس پر لوگوں کا غصہ برقرار ہے۔ حکومت کو بھی اس کا احساس ہے کہ یہ تحریک دوبارہ زور پکڑ سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاہین باغ میں پولیس آج بھی پہرہ دے رہی ہے۔ کسانوں کی طرح اس تحریک کو بدنام کرنے کے لیے بھی تمام ہتھکنڈے اختیار کئے گئے۔ عالمی شہرت حاصل کرنے والی اس تحریک کو جزی کی کامیابی تو حاصل ہوئی، لیکن اس کے اہم کرداروں کی گرفتاری نے اس کی دھار کسی حد تک کمزور کر دی۔ ضرورت اس بات کی ہے شہریت ترمیمی قانون میں کی گئی فرقہ وارانہ ترمیم کو رد کرانے کے لیے ایک بار پھر حکومت کو مجبور کیا جائے۔ بہتر یہی ہوگا کہ حکومت اس قانون کو بھی زرعی قوانین کی طرح از خود واپس لینے کا اعلان کرے۔ زرعی قوانین کی واپسی میں ان لوگوں کے لیے بھی ایک سبق پوشیدہ ہے جنہوں نے شہریت ترمیمی قانون کے خلاف تحریک میں حصہ لیا تھا۔ اس کا

سب سے اہم سبق یہی ہے کہ جمہوری نظام میں اتحاد و اتفاق اور صبر و تحمل سے ہی تحریکیں پروان چڑھتی ہیں۔ سی اے اے قانون کے خلاف عوامی تحریک کسی قیادت اور رہنمائی کے بغیر اپنے عروج تک پہنچے گی۔ مسلمانوں کی مذہبی اور سیاسی قیادت اس میں ایک تماش بین کے طور پر شریک ہوئی۔ اس نے اپنی مصالحتوں کے تحت اس میں کوئی سرگرم کردار ادا نہیں کیا۔ کسان تحریک کی کامیابی کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ ہمیں اپنے مسائل حل کرنے کے لیے حکمت عملی اور صبر و تحمل کے ساتھ میدان میں ڈٹے رہنا ہوگا۔ خدا اعتمادی اور خود اعتمادی کے ساتھ پیش قدمی کرنے سے ہی مسائل کا حل نکلے گا۔ ہر طرح کا خوف اور کمزوری دل سے نکالنا ہوگی۔ ہم اپنے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کر کے ہی منزل کے قریب پہنچ سکتے ہیں۔ یہی کسان تحریک کی کامیابی کا سب سے بڑا سبق ہے۔

شیر میسور ٹیپو سلطان کی رواداری

شکر آچار یہ لو کہ لکھے گئے خطوط میں ایک خط میں ٹیپو نے ان سے درخواست کی وہ پوری کائنات کی بھلائی اور خوشحالی کے لیے دعا کریں اور ان سے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ جگت گرو ہیں جس ملک میں آپ جیسی مقدس ہستی موجود ہو، وہاں خدا کی رحمت ہوتی ہے، آپ کو ایک غیر ملک میں اتنے زیادہ عرصے رہنے کی کیا ضرورت ہے، جلد فارغ ہو کر میسور واپس آجائیے۔ ٹیپو نے ہندو مناد کو خاص طور پر سری وینکٹ رمن، سری نواس اور سری رنگا ناتھ کی زمینیں اور دیگر دوسری چیزوں کی شکل میں پیش قیمتی تحفہ عطا کئے۔ کچھ مندر اس کے محلات کے آس پاس واقع تھے جو اب بھی اس کی آزاد خیالی، بفر اخذی، سخاوت اور رواداری کی شہادت دیتے ہیں۔ وطن اور قوم کے شہیدوں میں اس حد تک بلند مرتبہ اور کوئی دکھائی نہیں دیتا جو آزادی کی خاطر شہید ہو گیا، اسے اپنی عبادت میں یکساں خدا کی پوجا کرنے والے ہندو مندروں کی گھنٹیوں کی آواز سے کبھی خلل محسوس نہیں ہوا وہ وطن کی بازیابی کے لیے لڑتا ہوا شہید ہو گیا اور دشمن (ٹیپو) کی جسد خاکی ان انجان فوجیوں کی نعشوں میں پائی گئی تو دیکھا گیا کہ موت کے بعد بھی اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ بہر کیف تاریخ کو اسی عہد کے زمان و مکان میں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا ٹیپو سلطان کے کردار اور اس کے نظریات کو اٹھارہویں صدی کے ضمن میں سمجھنا چاہیے، جب ہر جانب شہنشاہیت کا بول بالا تھا۔ تاجرفرنیکوں نے کیتھولک مشنری کو سلطنت خداداد کے خلاف بھڑکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، چنانچہ ٹیپو کو ان کی سرکوبی کے لیے سخت قدم اٹھانے پڑے۔ علاوہ ازیں شیر میسور نے کیرالا میں واقع ایک چھوٹی سی ریاست ٹراؤ کور میں راج ایک انسانیت سوز روایت کے خلاف ایک انقلابی قدم اٹھایا، جہاں دولت اور پچھلی ذات کی خواہش کو ایک ساڑھی میں ہی جسم ڈھانپنا پڑتا تھا وہ بلاؤ نہیں پہن سکتی تھیں جب یہ خیر ٹیپو کے کانوں تک پہنچی تو انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں کپڑے سلوا کر دولت خواتین میں تقسیم کروائے اور انہیں بھی سماج میں ایک معزز فرد کی طرح جینے کا حوصلہ عطا کیا۔ ٹیپو کی دولت نوازی اعلیٰ ذات کے لوگوں کو ایک نظر نہیں بھائی۔ جس کی پاداش میں انگریز تاریخ دانوں کے ساتھ بعض کج نظر ہندوستانی مورخین نے بھی انہیں بدنام کرنے میں آسمان زمین کے قلابے ملا دیے، جس کا نتیجہ آج سب کے سامنے ہیں۔

آج ملک کے حالات کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں، سیاست اور کچھ فرقہ پسند تنظیمیں اس ملک کے امن و امان کو نذر آتش کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ ملک میں پچھلے سات سالوں سے نفرت کا جو بیج بویا جا رہا تھا مسلسل مخالفت اور دشمنی کی آپاشنی سے وہ فصل اب سرسبز و شاداب ہو کر لہلہا رہی ہے۔ جہاں یہ ملک محبت، پریم، ایکٹا اور بھائی چارے کے سبب اپنی لونگا جمنی تہذیب سے زمانے بھر میں منفرد پہچان بنائے ہوئے تھا۔ وہیں محبت کی پرستار یہ سرزمین ہند آج نفرت کا لاوا اگل رہی ہے۔ ملک میں ہر سوسطبہ خاص سے دشمنی اور مخالفت کا شور برپا ہے۔ کسی کو مسلمانوں کی اذان سے پریشانی ہے تو کہیں نماز سے تکلیف، کبھی مسلمانوں کو ملک کا غدار کہا جاتا ہے تو کبھی جہادی۔ افسف خدا یا یہ میرا ملک نفرت کی کس ڈگر پر چل پڑا ہے۔ ان سب پر مرہم رکھنے کی غرض سے کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو اس ملک میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہندو مسلمانوں کا ڈی این اے ایک ہی ہے، اور محبت کے ساتھ سب سے گہرا تیر یہ مارا جاتا ہے کہ ہندوستان میں اسلام نے مسلم حملہ آوروں کے ذریعہ تشکیل پائی۔ آریس ایس صدر کے اس بیان کا جہاں تمام نے خیر مقدم کیا وہیں اس حساس قلب کو بڑی کوفت محسوس ہوئی۔ آخر کیوں مسلمانوں پر اس طرح الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کو غیر کہنے والے سمجھ لیں کہ اسلام کی جڑیں اس مٹی میں اس طرح پھیلی ہوئی ہیں کہ اگر انہیں کھود کر نکلنے کی کوشش کی تو تمام ملک اکھڑ جائے گا۔ تاہم مسلمانوں کو اس مٹی سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ بھارت وہ ملک ہے جس سے ہزاروں سال سے مسلمانوں کے رشتے استوار ہیں۔ تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں تو انہیں علم ہوگا کہ ہمارے اور تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے اس دنیا میں اتارا گیا تو جس جگہ آپ نے اپنے قدم ناز کو رکھا وہ ملک ہندوستان کی سرحدی پھاڑی تھی۔ (جونی الحال سری لیکا میں موجود ہے)۔ اس وقت کوئی ملک آباد نہ تھا صرف اور صرف

دین اسلام مساوات کا پیامبر

آپ کی ذات اس سرزمین پر موجود تھی۔ یا پھر ہم انسانوں کی ماں حضرت حوا رضہ اللہ تعالیٰ عنہا تھیں کیونکہ سری لیکا کوئی بہت بڑا ملک نہیں ہے بلکہ جزیرہ نما چھوٹا سا ملک ہے اس لیے ہمیشہ سے وہاں ایک مستقل حکومت قائم رہی۔ اگرچہ وہاں کا حکمران ہندوستانی بادشاہ کے زیر تسلط رہتا لیکن صرف برائے نام۔ پہلے اس جزیرے کو سری لیکا کی بجائے صرف لیکا کہا جاتا تھا۔ اور اہل ادب اور ایران اسے "سرندیپ" کہتے تھے۔ طلوع اسلام سے پہلے عرب اور ایران تجارت کی نیت سے اس جزیرے پر آیا کرتے تھے۔ پھر جب اسلام کا ستارہ طلوع ہوا اس کے بعد بھی تجارت کا سلسلہ حسب سابق باقی رہا۔ اسلام بہت کم وقت میں سب سے بڑے پیمانے پر پھیلنے والا مذہب ہے۔ دین کی اصولی تعینات اور بنیادی عقائد حضرت آدم علیہ السلام سے لیکر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی طرح کے ہیں صرف احکام شرعیہ میں فرق رہا ہے۔ اور باعتبار عقائد اسلام کا وجود حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی قائم ہو گیا تھا چنانچہ مسلمان حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک قدم کی زیارت کے لیے بھی یہاں آنے لگے۔ اس وقت مذہب اسلام اپنی رعنائیوں سے دنیا کے بہت بڑے حصے کو منور کر رہا تھا نیز مسلمان کے اخلاق و کردار میں وہ جاذبیت تھی جو

غیروں کو اسلام کی حقانیت تسلیم کرانے کے لیے کافی تھی۔ تو کس طرح ممکن تھا کہ یہ جزیرہ ان کے اخلاق و کردار اور مذہب اسلام سے متاثر نہ ہوئے بغیر رہ جاتا جب کہ یہاں حقانیت و وحدانیت کے اولین علمبردار کی اولین برکات پہلے سے موجود تھے۔ 600 عیسوی کے لگ بھگ رسول اللہ کی پیدائش سے بہت پہلے عرب لوگ تجارت کے ذریعے بھارت کے رابطے میں تھے عرب تاجر باقاعدگی سے بھارت کے مغربی ساحلوں پر سامان تجارت بیچتے تھے جیسے مصالح جات سونا اور افریقی سامان وغیرہ۔ جب عربوں نے اسلام قبول کیا تو قدرتی طور پر اسلام نے عرب تاجروں کے ذریعے بھارت میں قدم رکھا اور انہیں تاجروں کے ذریعہ 628 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی ہندستان کی پہلی مسجد کی را کے کوڈنگورتا لوک کے میتھلا گاؤں میں قائم ہوئی۔ ہندستان کی یہ پہلی مسجد چیراں مسجد کے نام سے دنیا بھر میں مشہور ہوئی یہ عرب کے باہر بننے والی دنیا کی پہلی مسجد ہے جو آج بھی پوری شان بان سے تاریخ کی شہادت پیش کر رہی ہے۔ کچھ مورخین کا ماننا ہے وزیر اعظم زیند رمودی کے شہر گجرات کی بنواڑا مسجد اس سے بھی قدیم ہے اس مسجد کا قبلابیت المقدس یعنی اسرائیل کی طرف ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینے ہجرت کے بعد یعنی 623 میں قبلہ بدل کر مکہ ہو گیا آج بھی عرب میں ایک مسجد موجود ہے جسے مسجد قبلتین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ برصغیر ہند میں مسلم فتوحات بنیادی طور پر 12 ویں صدی سے 16 ویں تک ہوئیں، حالانکہ اس سے قبل کی مسلم فتوحات میں آٹھویں صدی میں راجپوت ریاستوں کے زمانے میں مہمات پر حملے تھے۔ لیکن تاریخ شاہد ہے ان حکمرانوں کا مقصد سلطنت کی وسعت میں اضافہ کرنا تھا، نئے نئے علاقوں کو اپنے اقتدار میں شامل کرنا تھا نہ کہ مذہب کی تشکیل۔ لیکن یہ سرزمین ہند کی خوش قسمتی کہ ان حکمرانوں کے ساتھ صوفیائے کرام کے مبارک قدموں نے اس سرزمین کو منور کر دیا۔ جہاں حکمرانوں کا مقصد سلطنت کی وسعت میں اضافہ کر کے حکومت کرنا تھا وہیں صوفیائے کرام کا مقصد دلوں کو جیتنا تھا۔

آپ کو کیا بتائیں، کن حالات سے ہمارا گذر ہوا۔ ٹھیک ہے لیکن آپ نے صلہ رحمی میں ہمارے حقوق سے کوتاہی برتی، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، ہر آتے جاتے چکروں میں ہم آپ کو نام نامی سلام عرض کرتے دور ہی سے سہی لیکن ہاتھ اٹھا کر آپ کی توجہ اپنی جانب ضرور مبذول کرواتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ کے اپنے گھر ہوئی تقریب میں آپ نے ہمیں نظر انداز کیا۔ بھائی میں واقعی بہت شرمندہ ہوں، آئندہ کسی بھی چھوٹی بڑی تقریب میں آپ کو نہیں بھولوں گا۔ اگر آپ بذات خود آسکیں تو ہم آپ کا انعام کر لیں گے شکم سیر کروا کر ہی آپ کی رہائی عمل میں آسکے گی۔ اتنی لچھے دار باتوں سے آپ اس سنگین جرم سے بچ نہیں سکتے۔ ہماری اس خفت کے وہ لوگ ذمہ دار ہیں جنہوں نے ازراہ ہمدردی ہماری مشکل حالات میں دعوت ناموں کی تقسیم کی ذمہ داری اپنے سر لی۔ خدا جانتا ہے کہ انہوں نے اس تقسیم رقعہ جات میں کتنی دھاندلیاں کیں اور ہمارے قریبی ملاقاتیوں سے پتہ نہیں کس وقت کی دشمنی بخوبی نکالی۔ اب اس میں ہمارا کیا تصور ہے آپ ہی بتلائیے کہ واقعی کیا ہم ایسی اچھی حرکت کر سکتے ہیں یا پھر دوسرے معنی میں ہم کسی سازش کا شکار ہوئے، بھائی میں شرمندہ ہوں۔ بار بار ایک ہی جملہ اعتراف کا پختہ ثبوت ہے۔ وہ تو سب ٹھیک ہے لیکن آپ کے لذیذ نان

وقلیہ سے ہم محروم رہ گئے۔ اس لئے آپ کو تعزیرات نان قلیہ کے تحت ڈھائی دنوں تک رسم دوتی سے دور رکھا جائے گا، نہ آپ ہماری طرف نظر اٹھا کر دیکھیں گے اور نہ ہی ہم آپ کی راہ خلوص پر قدم رنجہ ہوں گے۔

اس طرح ڈھائی روزہ سزا برائے تلی کا آغاز فی الفور عمل میں آگیا یا ہم اپنے ایک دیرینہ دوست سے ڈھائی دنوں کے لئے دور ہو گئے۔ یہ ڈھائی دن ہمارے لئے نہ ٹٹنے والی آفت ثابت ہوئے۔ ہمارے روزمرہ کے معمول میں مجرم دوست کو پابندی سے علیک سلیک بھی شامل تھا جو ان ڈھائی دنوں کے لئے منقطع ہو گیا تھا۔ ہم دکان کے سامنے سے دل مضطرب کی نگاہ شفیقانہ ڈالتے، تیز رفتاری کا مظاہرہ کرتے کن اکھیوں سے دوست کی شرمندگی سے لطف اٹھاتے۔ بے چارے ڈھائی دن کے اختتام سے قبل ہی ہماری راہ میں حائل ہو گئے۔ شرمندگی کی چادر کو اپنے چاروں طرف اچھی طرح لپیٹتے ہوئے وہ گویا ہوائے بجد اس میں ہماری ذرا بھی خطا نہیں ہے جو آپ ہم سے خفا ہیں آپ تو اچھی طرح واقف ہیں کہ تنہا انسان کتنی ذمہ داریوں کے ہوجھ تلے دبا ہوتا ہے۔ کدھر کدھر خیال رکھنا۔ اتنے میں ہمارے کانوں میں آں میاں کی سرگوشی سنائی دی۔ یہ وہی آں میاں ہے جو مشتاق احمد یوسفی کے ہمراہم زرا عبد او دوو بیگ اور سعید زیدی کے ہمراہ کاب عبد المنان کے قبیل کے ہیں۔ یہ ہمارے ہم نوالہ ہم پیالہ شیدائی نان قلیہ ایک خیالی کردار ہے۔ چلتے چلتے آپ کے علم میں یہ بات لے آئیں کہ اگلے مضمون میں آں میاں کا مکمل تعارف مدعا کار ناموں کے پیش کیا جائے گا۔ آں میاں کی سرگوشیاں آواز جھوٹ بولتے ہیں یہ صاحب، بھرے پرے خاندان میں بھدکتے ہوئے ہم نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اپنے جرم کی پردہ پوشی کے بہانے یہ تپتی لگی ناپنے کی ناکام کوشش میں ہیں۔ آپ ان کی طوطا چیمپی پر نہ چنائیں۔ ہم نے آں میاں کو خاموش رہنے کا اشارہ دیا۔ اوہ! میاں! اوہ بابا! ذرا بات کو سمجھو میرے یار۔

ہمارے دوست کے معصوم چہرے پر چھائی مردنی ہم سے دیکھی نہ گئی۔ جوان کی بے

گناہی ثابت کر رہی تھی۔ ہم نے ازراہ ہمدردی ان کا ہاتھ تھاما اور قریب کی ایرانی ہوٹل میں داخل ہو گئے۔ اب انہیں صحیح درس دینے کا وقت آ گیا تھا چونکہ ان کی ابھی تین اولادیں سہرے کے پھولوں کی خاطر قطار میں کھڑی تھیں، اس لئے آئندہ ایسی فاش غلطی کے مرتکب ہونے سے پہلے انہیں یہ سمجھانا ضروری تھا کہ شادی بیاہ کی تقریبات میں دوسرے تمام مراحل پر تقسیم دعوت ناموں کو فوقیت دی جانی چاہئے۔ اس کے لئے بذات خود فہرست رشتہ دار دوست احباب کو اول وقت یعنی رشتہ طے ہوتے ہی شروع کر دینی چاہئے تاکہ فاضل وقت میں آپ کو بھولے بسرے کی یاد آجائے۔ تیار شدہ فہرست کو کتابت رقعہ جات لکھوئی کے سامنے بیٹھ کر کتابت کے مرحلے طے کریں، اس میں کاتب کے ناشتے چائے پانی اور بیڑی سگریٹ کا خاص خیال رکھیں۔ ان تمام اشیاء کی فراہمی کے بعد ہی

جناب مولیٰ عرفیت اور پتے کے ساتھ رقعہ جات کی کتابت کا مکمل بخوبی جاری رکھتے کہ آپ حیرت کی سمندر میں کئی بار غوطہ زن ہو جاتے۔ اس طرح اس اہم کام کے بعد ان کی صحیح تقسیم کا عمل شروع ہوتا ہے۔ آپ کے گھر کی تقریب میں سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ بذات خود دعوت ناموں کو

حقداروں تک ایمانداری سے پہنچائیں۔ اس میں آپ کی عزت ذرا ہی بھی خراج نہیں ہوتی بلکہ بڑھ جاتی ہے۔ لوگ گھر آئی دعوت کو سرا آنکھوں پر بٹھا کر ٹھنڈے گرم سے آپ کے خاطر تواضع کرتے اور شرکت کو ممکن بنانے کا یقین دلاتے، صحیح عمل ہے۔ نہ کہ اونٹ پر بیٹھ کر بکریاں بانگنا۔ اس میں ایک اہم نکتہ پر توجہ دلانا ضروری سمجھتے ہیں کہ نقل زدہ مکانوں کے درپچوں سے دعوت ناموں کو داخل کرنا معیوب ہے۔ اس میں صاحب خانہ کی بے عزتی مضمر ہوتی ہے بلکہ ایک سے زائد چکروں کے بعد دست مبارک کے سپرد کرنا چاہئے۔ اب آئیے دعوت نامہ کی خاص اٹاخص تحریر کی طرف جو جلی حرفوں میں ہوتی ہے: آپ کی شرکت محفل عقد و طعام کے آرزو مند! یہ وہ تحریر ہے جو بذات خود دعوت دیتی ہے کہ کوئی آپ کی شرکت کے آرزو مند ہے۔ یہ جتنی اہم ہے وہ عملی اعتبار سے طعام گاہ میں دو درون تک نظر نہیں آتی۔ سید تانے آؤ یاد بے پاؤں تشریف لائیں، کھاؤ بیو اور جاؤ۔ خالہ ماں کا گھر جیسا حال ہوتا ہے۔ ہماری دعوت بھی شکم سیر ہو گئے کون کس کی پرواہ کرتا۔ آرزو مند الگ بھدکتے پھرتے۔ رتنے والے اپنی جان پیمانہ میں تزی گوشت سے لالباں کٹوروں اور تندور سے برآمد گرم نان کو بے آسانی چلاتے۔ داعی کو طعام گاہ کی فلسفگی کی خبر تک نہیں ہوتی۔ گھریلہ تو تب اجاگر ہوتا ہے جب کھانا کم پڑنے کی افواہ پھیلتی ہے۔ اس وقت داعی کی حالت اگم ٹکس کے چھاپے میں گھرے جیسی ہوتی ہے۔ آئے اور نمبر کے لئے غریب نوجوانوں کو دوڑایا جاتا، جب کہ وہ فیشن شو سے اپنی غیر موجودگی کسی قیمت میں برداشت نہیں کرتے۔ لیکن ماموں جان کی صورت دیکھ کر لالچالہ تقریب سے چند لمحوں کے لئے دوری بنا لیتے ایسے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آرزو مند اور متمنی حضرات جو دعوت نامہ میں اپنے ناموں کو زبردستی ٹھونکتے وہ باب داخلہ، اندرون طعام گاہ اور بیرونی راستہ پر کڑی نظر رکھتے ہیں۔ اس میں ایک چیز پر اور خاص خیال رکھنا چاہئے کہ رسد و سترخوان کی زینت بننے کی بجائے کہیں ڈبوں اور ٹھیلیوں کے ذریعہ ایک سپورٹ ٹونہیں ہو رہی ہے۔ عمل نکاسی بھی اس کی اہم وجہ ہے، اس پر بھی کڑی نظر رکھنی چاہئے۔ ہماری شادی خانہ کے منتظمین سے گدازش ہے کہ وہ تین حساس مقامات پر سی سی ٹی وی کیمروں سے نگرانی کا انتظام کریں اور اس علیحدہ سے اجرت شادی خانہ کے کرائے میں جوڑ دیں۔

بھائی! میں شرمندہ ہوں

ہندوستان میں انتہا پسندی عروج پر

ہندوستان میں مدت دراز سے فرقہ پرست طاقتیں مسلمانوں کو کچلنے اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ یہ سلسلہ کانگریس کے آخری عہد حکومت سے شروع ہوا اور بی جے پی کے دور اقتدار میں ان کوششوں نے تحریک کی صورت اختیار کر لی۔ ابتدائی طور پر یہ یوں ہوا کہ پردہ سیمیں کو مسلمانوں کے خلاف اور نوجوان نسل کے دل و دماغ میں نفرت کا زہر بھرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ 1990ء کے بعد زیادہ تر فلموں میں بد معاش، مافیا اور دہشت گردوں کے کردار مسلمانوں پر مبنی ہوتے تھے۔ رفتہ رفتہ یہ ہوا کہ زیادہ تر فلمیں جو وطن پرستی کے جذبات پر مبنی ہوتی تھیں، ان میں مسلمانوں کو 'وطن مخالف' اور غدار کی طرح پیش کیا جانے لگا۔ اسی دور میں حقیقت پرست فنکار بھی تھے جنہوں نے اس سازش کو سمجھا اور حقیقت پر مبنی فلموں کو فروغ دیا۔ ان کی فلموں میں فرقہ وارانہ فسادات کی حقیقت کو بے نقاب کیا گیا جس پر فاشٹ طاقتوں نے پردہ ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے باوجود فلموں میں مسلمانوں کی کردار کشی اور تاریخی و سماجی حقائق کو مخ کرنے کی جدوجہد جاری رہی۔ بد معاشوں اور دہشت گردوں کے نام ایسے افراد کے ناموں پر رکھے جانے لگے جو مسلمانوں کے یہاں مقدس اور محترم سمجھے جاتے ہیں تاکہ ہندوستان کی موجودہ نسل ان ناموں سے متاثر ہو جائے۔ بی جے پی کی اقتدار میں آمد کے ساتھ ہی فاشٹ طاقتوں نے فلم انڈسٹری کو زعفرانی انڈسٹری میں بدل دیا اور استعماری طاقتوں کے ساتھ مل کر پردہ سیمیں کے ذریعہ تہذیبی و ثقافتی یلغار کا دوسرا دور شروع ہوا۔ کرن جوہر کی مائی نیم اور قرآن اس سلسلے کی اہم کڑیاں ہیں۔ اس کے بعد 'پدمات'، 'بے بی'، 'کیسری'، 'تھاناجی، دی، واریر'، اور 'سوریہ نئی' جیسی بڑے بجٹ کی دیگر فلمیں شامل ہیں۔ آج تقریباً ہر دوسری فلم میں مسلمانوں کے خلاف منظم بیانیہ پیش کیا جا رہا ہے تاکہ فلم بین طبقے کے دل و دماغ میں نفرت کا زہر گھول دیا جائے۔ اس کے لیے ناکام اور کم شہرت یافتہ اداکاروں کا انتخاب کیا گیا۔ مثال کے طور پر اکشے کمار جو مسلسل ناکامی کے بعد ذہنی دباؤ میں تھے

انہیں پروپیگنڈہ فلموں کا ہیرو بنا کر پیش کیا گیا۔ کنگنا رناوت جس کو اداکاری کے بجائے اس کی زہرا فاشانی کے لیے پدم شری اعزاز سے نوازا گیا اس کی دوسری مثال ہے۔ اسی طرح آجے دیوگن جیسے دیگر معتدل مزاج اداکاروں کو بھی زعفرانی رنگ میں رنگ دیا گیا۔ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ اگر کسی ناکام اداکار کو کامیابی کے زینے طے کرنے کی خواہش ہے تو وہ اکشے کمار کے نقش قدم پر چلنے ہوئے فریقانی و زعفرانی تنظیموں کا آلہ کار بن جائے اور ان کے پروپیگنڈہ سنیما کا حصہ بننے میں تامل سے کام نہ لے۔ بوقت ضرورت انہی اداکاروں کا استعمال انتخابی تشہیر اور دیگر جگہوں پر بھی ہوتا ہے جس طرح پریش راول اور انوپم کھیر کا بہترین استعمال کیا گیا۔

زعفرانی تنظیموں نے سنیما سے بڑا حملہ میڈیا کی آزادی پر کیا۔ کیونکہ ہندوستان کا ایک طبقہ سنیما میں رغبت نہیں رکھتا مگر ہر طبقہ کسی ناکسی صورت میں میڈیا سے دلچسپی ضرور رکھتا ہے۔ اس لیے میڈیا کو منسوبہ بندسازش کے تحت کارپوریٹ گھرانوں کے حوالے کر دیا گیا تاکہ میڈیا کی آزادی پر قدغن لگا دیا جائے۔ میڈیا کے تمام تر بڑے اداروں پر کارپوریٹ کا تسلط ہے اور چینلوں پر وہی Content نشر کیا جاتا ہے جو ان کے مفادات کے خلاف نہ ہو۔ آج نیوز چینل اربوں روپے کے اشتہارات حاصل کر رہے ہیں۔ بدلے میں وہ Content نشر کیا جا رہا ہے جو کارپوریٹ کمپنیوں کے مفادات پر مبنی ہے۔ ان تمام تر کمپنیوں کے مالکان اور عہدیداران ایک مخصوص طرز فکر کے مبلغ اور سرمایہ گذار ہیں۔ اس لیے زیادہ تر نیوز چینلوں پر 'دیش بھکتی' کے نام پر اقلیتی طبقات کے خلاف نفرت انگیزی کی جاری ہے۔ بحث و مباحثہ (Debate) کے نام پر فرقہ واریت کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ نیوز چینل کا اینکر سوال کرنے کے بجائے جانبداری کے ساتھ خود

بحث میں فریق کی حیثیت سے شامل ہوتا ہے اور چیخ چیخ کر طے شدہ اسکرپٹ کے مطابق گفتگو کرتا ہے۔ ہندوستانی سیاست اور سماج کی بے راہ روی میں میڈیا کے کردار کو فراموش نہیں کیا جاسکتا۔ میڈیا جب سوال کرنے، بجائے ایک فریق کی حیثیت سے بحث و مباحثے میں شریک ہو تو سمجھ لیجیے جمہوریت کا ستون اکھڑ چکا ہے۔ ان نیوز چینلوں نے 'دیش بھکتی' کے نام پر زعفرانی سیاست کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا اور مسلمانوں کو اچھے اور برے مسلمان نیز ملک کے وفادار اور غدار مسلمان کے طور پر تقسیم کر دیا۔ آج پورا ملک ان کے تیار کردہ بیانیہ کی گرفت میں ہے اور اس مسلمان کو وطن پرست تسلیم کیا جاتا ہے جو زعفرانی ایجنڈے کے مطابق عمل کر رہا ہو۔ البتہ سوشل میڈیا پر موجود بعض چینلوں نے آزادی اظہار کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے میڈیا کے وقار کو بحال کرنے کی کوشش کی ہے اور کسی بھی طرح کی دھمکیوں سے خوف زدہ نہیں ہوئے، یہ ایک خوش آئند خبر ہے

وقف ٹوڈے

ہندی وار دو، ماہ نامہ، لکھنؤ

جلد نمبر ۱، شمارہ نمبر ۳، قیمت ۲۵ روپے صفحات ۳۲

مالک، پرنٹر اور پبلیشر جاوید احمد نے ایف، آئی

۱۲۹ / ۲۳ علوی ہاؤس کھنڈاری لین، لال باغ

لکھنؤ (یو پی) سے چھپوا کر، فلیٹ نمبر، ایس-۱ سیکنڈ

فلور، ۹۸ شبنم بلڈنگ، نظر باغ، لکھنؤ، اتر پردیش

سے شائع کیا ہے۔

موبائل نمبر: 7054337542

نوٹ: پی، آر، بی ایکٹ کے تحت کوئی بھی قانونی کارروائی

صرف لکھنؤ کی عدالت میں ہی کی جاسکتی ہے۔

وقت کی اہم ترین ضرورت

مفتی احمد عبید اللہ یا سرقاسمی

رسول رحمت، سید الاولین والآخرین امام الانبیاء و المرسلین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ﷺ کی ذات گرامی ایک ایسی کامل و اہل اور عظیم ترین شخصیت ہے کہ آپ ﷺ کی جامعیت و کاملیت اور عالمگیریت نے کائنات کے ہر ذرے، ہر گوشے اور ہر شعبہ حیات کو متاثر کیا، عبادات ہو یا معاملات، اخلاقیات ہو یا معاشرت، عدالت ہو یا سیاست، ریاستی احکامات ہوں یا سفارتی تعلقات، جنگی تدابیر ہوں یا گھریلو مسائل، تمام میں رسول رحمت ﷺ کی ذات والا صفات کامل و اہل نمونہ کے طور پر سامنے آتی ہے، رسول رحمت ﷺ کی سیرت طیبہ حیات انسانی کے تمام گوشوں پر محیط دکھائی دیتی ہے عہد رسالت سے قبل حیات طیبہ میں ایک امانت دار تاجر، بہترین شوہر، اچھا دوست، پیسوں کا در یتیم، بیواؤں اور مساکین کا غمخوار اور امانت و صداقت کے علمبردار نظر آتا ہے تو وہیں بعثت نبوت کے بعد ایک عظیم الشان داعی، غزوات اور سرایا میں ایک زبردست کمانڈر و سپہ سالار، ریاست مدینہ کا مایہ ناز سربراہ، ایک کامیاب جج، ایک کامیاب معلم، ایک کامیاب رہبر، ایک کامیاب سیاسی قائد کی ذات گرامی دکھائی دیتی ہے سیرت نبوی اسلام کا دائمی معجزہ یہ اس لیے کہ سیرت نبوی اسلام کا دائمی معجزہ اور اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہے کہ ہر نوع اور ہر آن تبدیل ہوتی ہوئی دنیا کے ہر کاب رہتی ہے، ہر دور اور ہر زمانے اوت ہر علاقے میں ہر طریقہ سے رشد و ہدایت کا منارہ نور بن کر بھٹی ہوئی انسانیت کو نشان منزل ہی نہیں بلکہ منزل دوام عطا کرتی ہے۔ کیا یہ سیرت نبوی کا معجزہ نہیں ہے کہ آج تک دنیا نے آپ

کی ذات بابرکات کو جس قدر قابل اعتناء و اہل اہتمام سمجھا اور جس خوبی اور حوصلہ و نیاز مندی کے ساتھ سیرت طیبہ کے ہر زاویہ کو سنوارا، اس اعزاز کا عشر عشر بھی کسی کے حصے میں نہیں آیا، کیا یہ سیرت نبوی کا اعجاز نہیں، یہ کہ آپ کی زبان کا ایک ایک حرف، حرکات و سکنات کی ایک ایک ادا، اور آپ کی جلوت و خلوت کے ایک ایک خط و خال کا عکس آج بھی موجود ہے اور آپ کی حیات طیبہ کی ایک ایک کیفیت کتب سیرت کے اوراق میں بالتفصیل محفوظ و مامون ہے۔

سیرت نبوی ﷺ قرآن کریم کی عملی توضیح

یہ اس لیے بھی کہ رسول رحمت ﷺ کی حیات طیبہ قرآن کریم کی عملی تفسیر و توضیح ہے قرآن اگر متن ہے تو سیرت اس کی تشریح، قرآن علم ہے تو سیرت اس کی عملی تطبیق، قرآن صحف و مابین الدتین اور اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہے تو سیرت اس زندہ و جاوید پیکر جمیل کا نام ہے جس نے سب کے گلیوں اور بازاروں میں چلتے پھرتے توحید کے نغمے سنائے اور مدینہ میں سلطنت مدینہ کی بنیاد رکھی جس نے اہل دنیا کو ایک منفرد طرز حکمرانی سے روشناس کروایا، یہی وہ حقیقت ہے جس کا اظہار امام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس طرح بیان کیا تھا کہ کان خلقہ القرآن کہ آپ چلتے پھرتے قرآن ہیں، انہیں وجوہات کے سبب خالق کائنات نے رسول رحمت ﷺ کو تاقیام قیامت آئیڈیل اور بہترین اسوہ بنا کر امت کے سامنے پیش کیا ارشاد باری ہے: درحقیقت تم لوگوں کے لئے اللہ کے رسول ﷺ میں ایک بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لئے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور لکھت سے

اللہ کو یاد کرے۔ (سورہ الاحزاب 21) اور رسول رحمت ﷺ کی اتباع اور اطاعت کو دراصل اپنی خوشنودی حاصل کرنے کا واحد ذریعہ قرار دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔ خدا بھی تمہیں دوست رکھے گا۔ (سورہ آل عمران 31) اور جو شخص رسول کی اطاعت کرے گا بیشک اس نے خدا کی اطاعت کی (سورہ النساء 81) ہماری بے حسی و مردہ دلی لیکن مقام افسوس کہ آج ہم جس طرح مطالعہ سیرت سے غفلت برت رہے ہیں اور اسکے پیغام ترین فراموش کر رہے ہیں وہ شاید اس دور کی تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے: ہمیں پتہ ہی نہیں کہ رسول رحمت ﷺ کے اخلاق و عادات کیا تھے؟ رسول رحمت ﷺ نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ اپنے دوستوں کے مابین رسول رحمت ﷺ کا کیا معاملہ تھا؟ کفار اور منافقین سے رسول رحمت ﷺ کا کیا رویہ تھا؟ ریاست مدینہ میں رسول رحمت ﷺ نے کیسی حکمرانی کی تھی؟ رسول رحمت ﷺ کی رحمت ورافت، محنت وشفقت، خشیت واناہت، شجاعت و امانت، صداقت و عدالت، وجود و خفا، فراست و متانت، ایثار و قربانی، احساس ذمہ داری، حلم و تواضع، صبر و توکل، نیز گھریلو زندگی میں بہترین ساتھی، شفیق سردار، مساکین کے سرپرست، اسی طرح قومی و ملی زندگی میں عدل و انصاف، فوجوں کی کمانڈری، انتظامات حکومت، رعایا پروری، سیاسی سوجھ بوجھ، دوستوں کی دلداری، دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک وہ عظیم اخلاق و کمالات کہ جسکی بنا پر رب العالمین نے رسول رحمت ﷺ کو خلق عظیم کے مرتبہ پر فائز کیا ان سے ہم نابلدن آشنا ناواقف ہیں۔

وقف ٹوڈے

ہندی واردو، ماہ نامہ، لکھنؤ

DECEMBER, 2021

